मां
दुर्गा ज्वेलर्स
सोने एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता
उचित ब्याज में गिरवी रखी जाती है।
शॉप नं.-69, सी-मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई
मो.-9424124911

सांध्य दैनिक
RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच
वर्ष- 17 अंक - 288 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 01 अगस्त 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

आवश्यकता है
बर्तन दुकान में काम करने के लिए
सेल्समैन, सेल्सगर्ल की आवश्यकता है।
पता - नेहरु भवन रोड, सुपेला, भिलाई, (छ.ग.)
मो.नं.-9827187008

खास-खबर

डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने राजधानी में कार्यशाला कल

रायपुर। न्याय व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सशक्त, सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आगामी 2 अगस्त 2026 को रायपुर स्थित होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल, वीआईपी रोड में नवीन आपराधिक कानूनों के माध्यम से डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाना विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय प्रणाली में डिजिटल तकनीकों के समावेश के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक दक्ष, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्रीविष्णुदेव साय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव तथा न्यायमूर्ति चंद्रवंशी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अन्य न्यायाधीशगण भी कार्यक्रम में सहभागी होंगे।

जुलाई में 2.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा जीएसटी संग्रह

नईदिल्ली। जुलाई 2026 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कुल संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा।सरकार की ओर से शनिवार को जारी मासिक जीएसटी राजस्व रिपोर्ट के अनुसार, यह जुलाई 2025 के 1.83 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 15.4 फीसदी ज्यादा है। यानी एक साल में जीएसटी संग्रह में 15.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी मजबूत घरेलू राजस्व और आयात से मिलने वाले कर में बड़ी वृद्धि के कारण हुई है। देश के अंदर होने वाले कारोबार से मिलने वाला घरेलू जीएसटी राजस्व जुलाई 2026 में 10.1 फीसदी बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया। जुलाई 2025 में यह 1.31 लाख करोड़ रुपये था। वहीं, आयात से मिलने वाले जीएसटी राजस्व में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आयात से मिलने वाला जीएसटी 28.8 फीसदी बढ़कर 66,511 करोड़ रुपये हो गया। इससे जुलाई महीने का कुल जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जीएसटी संग्रह के नए आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद देश में घरेलू खपत और कारोबार की गतिविधियां स्थिर बनी रहीं। घरेलू कारोबार और आयात से मिलने वाले ज्यादा कर संग्रह ने कुल राजस्व बढ़ाने में मदद की है।

आईआईटी दिल्ली के CEEE प्रोग्राम के लिए भिलाई के युवा शिक्षाविद् प्रभात कुमार का चयन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। शिक्षाधानी भिलाई के युवा शिक्षाविद् व सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर प्रभात कुमार प्रसाद ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनका चयन देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली द्वारा आयोजित Centre for Engineering Education E&cellence (CEEE) Programme (CEEE) 2026-27 के लिए हुआ है। यह उपलब्धि न केवल भिलाई बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। देशभर के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों से चयनित सीमित सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी सदस्यों में प्रभात कुमार प्रसाद ने अपनी जगह बनाई है।

छह माह का यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम Indian National Academy of Engineering (INAE), Infosys Foundation तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के सहयोग से जून से दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य इंजीनियरिंग शिक्षकों की शिक्षण दक्षता,

अनुसंधान क्षमता, नवाचार, डिजिटल शिक्षण तकनीकों एवं अकादमिक नेतृत्व कौशल को सशक्त बनाना है। इस दौरानआईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आधुनिक इंजीनियरिंग शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रभात कुमार वर्तमान में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई में सिविल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय संस्थान के चेयरमैन श्री आनंद त्रिपाठी, प्राचार्य डॉ. अजय तिवारी तथा उप प्राचार्य डॉ. रविंद्र शर्मा को देते हुए कहा कि उनके सतत मार्गदर्शन, विश्वास और प्रोत्साहन से ही यह सफलता संभव हो सकी। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के सिविल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) वसंत मत्सागर एवं उनकी पूरी टीम के प्रति भी आभार व्यक्त किया। इस उपलब्धि पर प्रभात कुमार प्रसाद के पिता जय बहादुर प्रसाद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का अवसर है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रभात भविष्य में भी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर भिलाई छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करेंगे।

कश्मीर में टारगेट किलिंग : छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों की आतंकी हमले में मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर/बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की आतंकी हमले में मौत हो गई। दोनों मजदूर कुलगाम जिले के केलाम इलाके में स्थित एक ईंट भट्ठे में मजदूरी करते थे जहां वे आतंकी हमले के शिकार हो गए। मौत के बाद छुईहा गांव में मातम पसर गया है तथा लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस हमले में पहले सक्ती जिले के मजदूर दीपक रात्रे की मौत हुई थी, वहीं गंभीर रूप से घायल सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छुईहा गांव निवासी भूपेंद्र कुमार भैना (28) ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

हमले के बाद भूपेंद्र कुमार भैना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शनिवार 1 अगस्त को उनके निधन की खबर गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया।

रोजगार की तलाश में गए थे दोनों

भूपेंद्र अपनी पत्नी कचरा बाई के साथ करीब तीन महीने पहले रोजगार की तलाश में कश्मीर गए थे। कुछ समय पहले ही वे गांव आए थे और फिर दोबारा ईंट भट्ठे में काम करने लौट गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। भूपेंद्र अपने दो वर्षीय बेटे मानस को गांव में अपनी छोटी बहन और दादी की देखरेख में छोड़कर मजदूरी करने गए थे। अब मासूम बेटे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। वहीं उनके माता-पिता दशरथ भैना और नागेश्वरी भैना भी पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

गांव में शोक का माहौल

छुईहा गांव में शोक का माहौल है। हर किसी की जुबान पर इस दर्दनाक घटना की चर्चा है। ग्राम पंचायत के सरपंच धनीराम बंजारे ने कहा कि पंचायत हरसंभव सहायता के लिए परिवार के साथ खड़ी है और दुख की इस घड़ी में पूरा गांव पीड़ित परिवार का सहयोग करेगा।

सीएम साय ने जताया शोक

कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों की मौत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों की मृत्यु की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मृतक श्रमिकों को विनम्र श्रद्धांजलि।

पीएम मोदी बोले- गुमराह बच्चों को माफ करना चाहता हूं, बचपन में गलतियां होना स्वाभाविक

नईदिल्ली ए.। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम लाइव के जरिए देशवासियों, खासकर युवाओं और जेन-जी को संबोधित किया। रात करीब 11 बजे प्रसारित अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ, उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गईं, लेकिन वह इस घटना को अलग नजरिए से देखते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होना स्वाभाविक है और उसी उम्र में सुधार का अवसर भी मिलता है। उन्होंने माना कि समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश है और यह सांस्कृतिक झटका भी है कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि

ऐसे बच्चों को समाज से अलग करने के बजाय उन्हें सही दिशा दिखाने की जरूरत है।

पीएम मोदी ने कहा कि गुमराह बच्चों को अदालतों के चक्कर कटवाने या समाज में प्रताड़ित करने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। उन्होंने कहा कि वह उन्हें माफकरना चाहते हैं और समाज से भी इस भावना को स्वीकार करने की अपील की। उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा कि जैसे कभी-कभी दांतों के बीच जीभ आ जाती है और चोट लग जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ते क्योंकि दोनों हमारे अपने हैं। उसी तरह ये बच्चे भी हमारे हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाना समाज की जिम्मेदारी है।

पीएम को अपशब्द कहने वाली लड़की ने मांगी माफी

पीएम मोदी के वीडियो के बाद जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाली लड़की का माफी मांगने का वीडियो वायरल है। लड़की ने वीडियो में खुद के नाबालिग होने की बात कही। वीडियो में उन्होंने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस गई थी, जहां प्रदर्शन चल रहा था। वहां कई समूह प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे थे। मैं उनके प्रभाव में आ गई और मैंने भी कई अनुचित बातें कह दीं। मैं केवल 15 साल की हूं। मैंने जो किया, वह माफी के लायक नहीं था। उन्होंने आगे कहा, यह मेरी पहली और आखिरी गलती है। मैं भविष्य में कभी भी इस तरह की बात नहीं कहूंगी और न ही कुछ पोस्ट करूंगी। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं। मुझे अपने किए पर गहरा शर्मिंदगी है।

इंडियन ओवरसीज बैंक घोटाले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक तमिलनाडू से गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बेमेतरा शाखा में हुए करीब 14 करोड़ 56 लाख रुपये के कथित घोटाले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और तत्कालीन शाखा प्रबंधक विनीत दास को तमिलनाडु के तंजावुर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर बेमेतरा लाया है। इस मामले में इससे पहले चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस जांच में सामने आया कि बैंक अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर करीब 180 खातों में संदिग्ध तरीके से ऋण स्वीकृत किए। कई मामलों में जिन इकाइयों के नाम पर लोन दिया गया, वे या तो अस्तित्व में ही नहीं थीं या पहले से बंद थीं। स्वयं सहायता समूह और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी निर्धारित सीमा से अधिक राशि स्वीकृत किए जाने के आरोप हैं। कई ऋण फर्जी जीएसटी दस्तावेज, नकली अभिलेख और बिना उचित मूल्यांकन के मंजूर किए गए।

कुछ मामलों में जिस जमीन को आधार बनाकर लोन दिया गया, वह उधारकर्ताओं के नाम पर ही दर्ज नहीं थी। इतना ही नहीं, मत्स्य विभाग के नाम पर कथित फर्जी स्वीकृति पत्र लगाकर भी ऋण स्वीकृत किए गए और सब्सिडी का दावा तक नहीं किया गया। इस पूरे प्रकरण की शिकायत वर्ष 2022 में बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक रज्जू पाटनवार ने दर्ज कराई थी। जांच के बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक विनीत दास सहित कमलेश सिन्हा, जोहन वर्मा, नागेश वर्मा और टीकाराम माथुर के खिलाफआपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी और गबन सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

बोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले- आंध्र के विकास का रनवे है नया एयरपोर्ट

■ 5000 करोड़ की लागत से बना है नया एयरपोर्ट, विशाखापट्नम में बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी

वैजाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे के निर्माण पर करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इस आधुनिक हवाई अड्डे को पूरे उत्तर आंध्र क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अहम मान रही है।

WELCOME TO BHOGAPURAM AIRPORT
WELCOME PM MODI JI CM CBN JI

सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद वह राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ हवाई अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री खुली छत वाले वाहन से जनसभा स्थल पहुंचे। वहां जनजातीय समुदाय की 13,500 से अधिक महिलाओं और छात्र-छात्राओं ने ढिमसा नृत्य करके उनका भव्य स्वागत किया।

आज का दिन स्वर्ण आंध्र के विजन के लिए बहुत अहम : पीएम

इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, स्वर्ण आंध्र के विजन के लिए बहुत अहम है। मुझे इस सुअवसर पर उत्तर आंध्र की इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा, आज यहां करीब 18 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हवाई अड्डे के साथ साथ ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश के सड़क संपर्क से भी जुड़ी हैं। इनमें उर्जा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक हैं कि आंध्र किस गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

ढिमसा डांस की प्रस्तुति को सराहा

उन्होंने आगे कहा, आज एक ओर विकास के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, साथ ही ढिमसा डांस का सास्कृतिक रिकॉर्ड भी रचा गया है। 13 हजार से ज्यादा आदिवासी बहनों और बेटियों की प्रस्तुति, उनका उत्साह, उनका अनुशासन और आदिवासी संस्कृति का गौरव... ये दृश्य वाकई अद्भुत था। इसमें देश की विविधता की झलक भी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजकर रखी गई जनजातीय विरासत भी थी। मैं इस प्रस्तुति के लिए आप सभी का और विशेष रूप से मेरी आदिवासी बहनों-बेटियों का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जिस धरती पर आदिवासी हितों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज उसी धरती पर आंध्र प्रदेश के एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। यह एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है। ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्चपैड है। मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

भारत के पास परखा हुआ नेतृत्व : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू

भोगापुरम में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश नए नेतृत्व की तलाश में संकट का सामना कर रहे हैं। भारत भाग्यशाली है कि उसके पास परखा हुआ नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूरे किए हैं और असाधारण काम किया है।

BOOK NOW!
Harsh Media
अब हर नज़र
आपके Brand पर !
- Unipole / Hoarding
- Outdoor LED Screen
- Digital LED Television
- Train Wrap Branding
- Mobile LED Vehicle
- Social media advt.
- News Paper advt.
- Branding consultancy
8253029444 | 8435918888
www.harshmediaadvertisers.com
info.harshmedia@gmail.com
harsh_media_advertisers

संपादकीय

बेरोजगारों को संबल

सीईटी पास युवाओं को मिलेगा काम और भत्ते

देश में युवा मन के सपनों और भविष्य की चिंताओं के मद्देनजर हरियाणा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कहीं न कहीं दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में हुए छात्र आंदोलन के बाद आज युवा सरकार की नीतियों के केंद्र में हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की नायब सरकार ने सीईटी पास युवाओं की सुध ली है। जाहिर है सभी सीईटी पास युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। कई युवा परीक्षा पास करने के बाद भी वर्षों तक बेरोजगार बने रहते हैं। एक्शन में आई हरियाणा सरकार ने ऐसे पांच लाख चालीस हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं की पहचान की है, जिन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद रोजगार नहीं मिला। इसके बाद 'विकसित भारत विजन 2047' के तहत रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तथा हरियाणा कौशल विकास मिशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर बल दिया कि कौशल विकास योजनाओं को सिर्फ प्रशिक्षण तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें सीधे रोजगार से भी जोड़ा जाए। सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी पास युवाओं को प्रति माह सौ घंटे का काम उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर यदि उन्हें दो साल तक रोजगार नहीं मिलता, तो सक्षम युवा योजना के तहत भत्ता दिया जाएगा। निश्चित रूप से सभी बेरोजगारों को काम व भत्ता देना व्यावहारिक भले नहीं लगे, लेकिन बेरोजगारों की बड़ी संख्या को फौरी तौर पर संबल जरूर मिलेगा। दरअसल, विगत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2016 में युवाओं के लिए एक ऐसी ही योजना लाई गई थी, जिसमें सालाना 1 लाख 80 हजार से कम आय वाले परिवार के युवाओं को 9 हजार का मासिक भत्ता देने की बात कही गई थी। वहीं, महीने में निर्धारित समय तक काम देने के भी प्रयास हुए थे। लेकिन वास्तव में ऐसी आदर्श योजना के क्रियान्वयन में व्यावहारिक दिक्कतों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता।

> “ कई युवा परीक्षा पास करने के बाद भी वर्षों तक बेरोजगार बने रहते हैं। एक्शन में आई हरियाणा सरकार ने ऐसे पांच लाख चालीस हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं की पहचान की है, जिन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद रोजगार नहीं मिला। इसके बाद 'विकसित भारत विजन 2047' के तहत रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तथा हरियाणा कौशल विकास मिशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर बल दिया कि कौशल विकास योजनाओं को सिर्फ प्रशिक्षण तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें सीधे रोजगार से भी जोड़ा जाए।

विगत में हरियाणा के युवाओं को प्रकृति से जोड़ने व रोजगार के अवसर मुहैया कराने के अभिनव प्रयास भी मनोहर लाल सरकार के दौरान हुए थे, जिसमें बेरोजगार युवाओं को पौधा लगाने का दायित्व दिया गया था। इसमें गड्ढे खोदने, पौधे लगाने और उनकी निरंतर देखभाल करने के लिए मानदेय निर्धारित किया गया था। उद्देश्य था कि जो पौधे लगें, वे जीवित भी रहें और युवा प्रकृति से जुड़ें। नायब सरकार की नई मुहिम इसी कड़ी का विस्तार माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, नायब सरकार समय की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा देने के प्रयासों में गंभीर नजर आती है। इसी कड़ी में एआई प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार पंचकूला व गुरुग्राम में एआई हब विकसित करने जा रही है, जिसके अंतर्गत दो लाख युवाओं को हाई-स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अंतर्गत एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, मॉडल आईटीआई और पॉलिटेक्निक में एआई प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं सामान्य स्कूलों व कॉलेजों में इस बात पर बल दिया जा रहा है कि छात्र व छात्राओं को व्यवसायपरक शिक्षा दी जाए, जिससे युवा सिर्फ नौकरियों के भरोसे न बैठे रहें और खुद का काम-धंधा शुरू कर सकें। विडंबना यह है कि 21वीं सदी में भी भारतीय युवा सरकारी नौकरी के सम्मोहन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। बढ़ती आबादी और घटती सरकारी नौकरियों ने इस संकट को बढ़ाया है। आज जरूरत इस बात की है कि छात्रों में नवाचार व कौशल विकास के जरिये आत्मनिर्भर बनने का जज्बा पैदा किया जाए, जिससे वे खुद ही आर्थिक रूप से सक्षम न बनें, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने की स्थिति में आ जाएं। आज वैश्विक स्तर पर जारी राजनीतिक अस्थिरता व सिमटते रोजगार के अवसरों के बीच देश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत युवाओं का देश है। यदि हम हर हाथ को काम न दे सके, तो युवाओं की शक्ति व क्षमताओं का लाभ उठाने के अवसर से वंचित हो जाएंगे।

आंदोलन ने दिया मीडिया को आत्ममंथन का मौका

विश्वनाथ सचदेव

जंतर-मंतर का ही यह दृश्य हमें सोचने की सामग्री दे सकता है। एक यू-ट्यूबर पत्रकार की जय के नारे लगा रहे थे, उसकी निष्पक्ष और साहसिक रिपोर्टिंग के लिए! ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो मीडिया की विश्वसनीयता को बचाने की कोशिश में लगे हैं। उनका अभिनंदन होना चाहिए।

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर विद्यार्थियों-युवाओं का आंदोलन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ भले ही समाप्त हो गया हो, पर उसकी गूंज एक लम्बे अर्से तक सुनाई देगी। इन तीस-पैंतीस दिनों के आंदोलन के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अर्से तक याद रखा जायेगा। इस बहुत कुछ में युवाओं द्वारा 'गोदी मीडिया' के विरुद्ध लगाये गये नारे भी हैं जिन पर स्वयं मीडिया वालों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस तरह मुख्यधारा के कुछ समाचार चैनलों के खिलाफ प्रदर्शनकारी आवाज़ उठा रहे थे वह अपने आप में मीडिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ मीडिया कर्मियों पर जिस तरह के हमले हुए, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। युवाओं को पूरा हक है कि वे मीडिया के प्रति अपने असंतोष का इज़हार करें, उनका गुस्सा भी जायज हो सकता है, पर पत्रकारों पर शारीरिक हमले का समर्थन नहीं किया जा सकता। यह सब कहने के बाद एक सवाल जो पूरी गंभीरता के साथ उठता है वह मीडिया की छवि का है। 'गोदी मीडिया' के नाम से मीडिया के जिस वर्ग को आज देश में जाना जा रहा है, वह कुल मिलाकर सरकार-समर्थक वर्ग ही है। सरकार की कमियों और अच्छाइयों दोनों को सामने लाना पत्रकारिता का काम है।

जनतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका बहुत स्पष्ट है यह भूमिका ईमानदार पहरेदारी की है। जनतंत्र का चौथा स्तंभ है यह पहरेदार और इस स्तंभ की सबसे बड़ी ताकत इसकी विश्वसनीयता है। समाज पत्रकार से यह अपेक्षा करता है कि वह जो देख-समझ रहा है उसे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ समाज के सामने रखेगा। यही उसकी निष्पक्षता का मानदण्ड है। था एक ज़माना जब अखबार में लिखे शब्द पर पाठक लगभग अंधविश्वास करता था। यह अंधविश्वास भी ठीक नहीं कहा जा सकता, पर इतना तो कहना पड़ेगा कि यह विश्वास पत्रकारिता की सबसे कीमती पूंजी और सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत कमज़ोर पड़ती दिखने लगी है! आवश्यकता यह समझने की है कि यह स्थिति कैसे आयी?

आज़ादी प्राप्त करने से पहले तक हमारे देश की पत्रकारिता का इतिहास कुल मिला कर समाज-सेवा का ही था। विशेषकर भाषाई पत्रकारिता का इतिहास। देश के पहले हिंदी अखबार का तो ध्येय वाक्य ही 'हिंदी जन के हेत' यानी 'हिंदुस्तानियों के हित के लिए' था। एक मिशन थी पत्रकारिता। यह स्थिति एक अर्से तक बनी रही, पर धीरे-धीरे सेवा की जगह सत्ता हमारी पत्रकारिता पर हावी होती गयी। जंतर-मंतर पर युवा प्रदर्शनकारियों ने जिस पत्रकारिता पर हमला किया था वह सत्ता वाली पत्रकारिता ही है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज देश की पत्रकारिता के एक बड़े वर्ग पर 'आंख मूंद कर सरकार-परस्ती' का आरोप लग रहा है। खुलेआम कहा जा रहा है कि देश के मीडिया का एक बड़ा वर्ग जैसे सरकार की गोद में जाकर बैठ गया है। इसी पक्षधरता का एक उदाहरण यह है कि युवाओं के इस आंदोलन के शुरुआती दौर में कई दिन तक हमारे समाचार चैनलों में कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियां रहस्यमय ढंग से गायब ही रही थीं। अखबारों में भी इससे सम्बंधित समाचार मुख्यत: भीतर के पन्नों पर ही जगह पाते थे। बाद के दिनों में जब युवाओं का यह आंदोलन लगातार व्यापक होने लगा तो किसी के लिए इसकी अनदेखी करना संभव नहीं रह गया था। तब शायद पहली बार मुख्यधारा के समाचार चैनलों के प्रतिनिधि 'कॉकरोच-आंदोलन' की ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे। और तब शायद पहली बार 'गोदी मीडिया' पर युवाओं का गुस्सा इतना प्रखर होकर सामने आया था।

हमेशा से पत्रकारिता की इज्जत रही है समाज में। मीडियाकर्मियों को अधिकांशत: आदर की दृष्टि से ही देखा जाता रहा है। आज जबकि पत्रकारिता मिशन की जगह व्यवसाय मात्र बन कर रह गयी है, अखबार को साबुन की टिकिया की तरह बेचा जा रहा है और देश का सबसे बड़ा 'मीडिया घराना' खुलेआम यह कहता दिखता है कि 'हम विज्ञापन का व्यापार करते हैं' तो समाज से यह अपेक्षा करना कि वह मीडिया की भूमिका को अतिरिक्त आदर के भाव से देखेगा, स्थिति को न समझने का उदाहरण ही माना जायेगा। और यदि पत्रकारिता एक विशिष्ट पेशा है तो मीडिया से यह आशा करना गलत नहीं होगा कि वह अपनी विशिष्टता की रक्षा के प्रति सावधान रहे। दुर्भाग्य से ऐसा होता दिख नहीं रहा। इसका ही परिणाम है कि आज हमारा मीडिया विश्वसनीयता के एक गहरे संकट से गुज़र रहा है। इस संकट के तीन बड़े कारण हैं व्यावसायिक दबाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सनसनीपरकता। इसके साथ ही 'सबसे पहले और सबसे आगे' का लालच भी मीडिया की विश्वसनीयता को कम कर रहा है।

घटती विश्वसनीयता का यह संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसके कारण कुछ भी रहे हों, पर यह स्पष्ट है कि मीडिया से जनता का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। पता लगायेंगे तो आपको ऐसे बहुत से पाठक और बहुत से दर्शक मिल जायेंगे जिन्होंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है अथवा टी.वी. पर समाचार देखना बंद कर दिया है। 'राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट' के वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले एक दशक में अखबारों, रेडियो और टेलिविजन समाचारों को पढ़ने-देखने में दो अंकों की गिरावट आयी है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि यह केवल नये लोगों द्वारा मीडियम न अपनाने के कारण नहीं है, बल्कि पुराने पाठक-दर्शक भी अब परम्परागत मीडिया से दूर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण विश्वसनीयता का घटना है।

ऐसा नहीं है कि जनता की समाचारों में रुचि नहीं रही। जानना चाहते हैं लोग, पर अब उन्हें यह भी समझ आ रहा है कि मुख्यधारा का मीडिया अब अपने पाठकों-दर्शकों के बजाए अपने मालिकों के हितों के प्रति ज़्यादा उदार है। ये मालिक सत्ता के पक्ष में खड़े रहने में अपना अधिक लाभ देखते हैं। आज सरकारें मीडिया को जितना लाभ दे रही हैं, वह हैरान कर देने वाला है। टी.वी. चैनलों पर सरकारी विज्ञापनों की भरमार देखकर यह बात सहज ही समझ आ जाती है कि हमारा मीडिया क्यों सरकारों से डरा-डरा रहता है। भारत सरकार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि 2014 से 2022 के बीच 6491 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किये गये। एक निजी चैनल को, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ चैनल बताता है, 15 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच दस करोड़ चौदह लाख रुपये के विज्ञापन दिये थे। ये आंकड़े चार-पांच साल पुराने हैं, पर बहुत कुछ बता रहे हैं। कल्पना की जा सकती है कि एक महीने में सरकार से करोड़ों रुपये पाने वाला समाचार चैनल क्यों सरकार को नाराज़ करना चाहेगा?

समाचार चैनलों की यह सरकारपरस्ती उनकी विश्वसनीयता को घटाने का एक बड़ा कारण है। शायद सबसे बड़ा। जंतर-मंतर में 'गोदी मीडिया' (समाचार चैनल) पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शायद इसीलिए फूटा था। जानकारी तो चाहिए जनता को, पर अब वह गलत और भ्रामक जानकारी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है।

सरकार या बाज़ार या भीड़ के दबाव में आकर गलत जानकारी देने वाले हमारे मीडिया को अब यह समझना ही होगा कि विश्वसनीयता उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। विश्वसनीयता खोकर वह कहीं का नहीं रहेगा। उस दिन जो गुस्सा राजधानी दिल्ली में फूटा था, उसमें कुछ पत्रकारों पर हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। वैसे भी, चैनल के पत्रकार तो अपने मालिकों के इशारों पर काम करते हैं। यह उनकी विवशता है। फिर भी जंतर-मंतर का ही यह दृश्य हमें सोचने की सामग्री दे सकता है। एक यू-ट्यूबर पत्रकार की जय के नारे लगा रहे थे, उसकी निष्पक्ष और साहसिक रिपोर्टिंग के लिए! ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो मीडिया की विश्वसनीयता को बचाने की कोशिश में लगे हैं। उनका अभिनंदन होना चाहिए।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सत्ता और जवाबदेही एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते

पवन के. वर्मा

2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जदयू को 40 में से 2 सीटें मिली थीं। जब उन्होंने इस पराजय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया, उस समय मैं उनके साथ था।

यह खबर फैलते ही पार्टी के नेता और विधायक उनके आवास पर पहुंच गए और उनसे निर्णय वापस लेने का आग्रह करने लगे। विधानसभा में जदयू के पास तब भी स्पष्ट बहुमत था और इस्तीफा देने की कोई संवैधानिक या राजनीतिक मजबूरी नहीं थी। लेकिन नीतीश अपने फैसले पर अडिग रहे। इसके बाद जीतन राम मांझी अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री बने।

हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब नेताओं ने माना कि सत्ता और जवाबदेही एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इसलिए पद छोड़ना ही उचित है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री हैं।

1956 में महबूबनगर रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने रेलमंत्री के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ऐसा न करने के लिए राजी कर लिया। लेकिन उसी वर्ष बाद में अरियालुर रेल दुर्घटना के बाद शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया।

दुर्घटना के लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं थे, फिर भी उनका मानना था कि मंत्रालय के प्रमुख होने के नाते इस विफलता की नैतिक जिम्मेदारी उन्हें ही लेनी चाहिए। उनका त्यागपत्र राजनीतिक शुचिता के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में गिना जाता है।

1958 में एलआईसी से जुड़े मुंद्रा कांड के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रश्न यह नहीं था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई अनुचित लाभ उठाया था। असली सवाल यह था कि क्या कोई मंत्री अपने मंत्रालय के कामकाज की जिम्मेदारी से स्वयं को अलग कर सकता है?

1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद वी.के. कृष्ण मेनन ने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बार फिर, यह इस स्वीकारोक्ति का प्रतीक था कि किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति संस्थागत विफलता के परिणामों से अनिश्चित काल तक स्वयं को अलग नहीं रख सकता।

1992 में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद माधवराव सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। 1999 में गैसल रेल दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद छोड़ दिया था।

इसी प्रकार, 2000 में पंजाब में हुई हावड़ा-अमृतसर मेल दुर्घटना के बाद ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। 26/11 के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने-अपने पद छोड़ दिए थे।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में पद जितना ऊंचा होता है, उसके साथ जुड़ी जवाबदेही भी उतनी ही अधिक होती है। निस्संदेह, प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से यह अधिकार है कि वे अपने मंत्रिमंडल में किसे रखना चाहते हैं, इसका निर्णय स्वयं करें।

किसी मंत्री का इस्तीफा ऐसा हथियार नहीं बनना चाहिए, जिसे विपक्ष हर प्रशासनिक विफलता के बाद लहराए। न ही केवल इसलिए किसी मंत्री की बलि दी जानी चाहिए कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ने उसकी मांग की है। यदि हर आरोप स्वत: ही पद से हटाने का आधार बन जाए, तो सरकार चलाना ही सम्भव नहीं रह जाएगा।

इसका दूसरा पहलू भी उतना ही चिंताजनक है- यह धारणा कि जब तक कोई अदालत, जांच एजेंसी या संसदीय समिति किसी मंत्री की व्यक्तिगत जवाबदेही स्थापित न कर दे, तब तक उसे पद पर बने रहना चाहिए। इससे मंत्रिस्तरीय जवाबदेही केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा बनकर रह जाती है।

लोकतंत्र इससे कहीं अधिक की अपेक्षा करता है। मंत्री कोई नौकरशाह नहीं होता। नौकरशाह प्रशासन चलाते हैं; मंत्री नेतृत्व करते हैं और राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यवस्था विफल हो जाए, तो केवल कुछ अधिकारियों को निलंबित कर देना और जांच समिति गठित करने की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। मंत्री को स्वयं से भी पूछना चाहिए कि क्या उसके पद पर रहने से व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होगा या कमजोर पड़ेगा।

धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर-लीक मामले में अंतत: इस्तीफा देकर सही कदम उठाया है। लेकिन उन्होंने इतनी देर क्यों की? अपनी और सरकार, दोनों की छवि के लिए उन्हें यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सार्वजनिक पद जवाबदेही से बचने की ढाल नहीं होते; बल्कि जवाबदेही का अस्तित्व ही सार्वजनिक पदों के कारण है।

मंत्री नौकरशाह नहीं होता। नौकरशाह प्रशासन चलाते हैं; मंत्री नेतृत्व करते हैं और राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हैं। व्यवस्था विफल हो, तो कुछ अधिकारियों को निलंबित करना और जांच समिति गठित करना काफी नहीं होता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

निरंतर बढ़ते प्लास्टिक कूड़े के निपटान की चुनौती

दीपिका अरोड़ा

पर्यावरण, जैव विविधता व सेहत के लिए प्लास्टिक कूड़ा गंभीर ख़तरा है। इसका समुचित निस्तारण प्रमुख चुनौती है। देश में रोज़ाना निकलने वाले क़रीब 60 फीसदी कूड़े की ही रिसाइक्लिंग होती है। बाकी बचा कचरा जल,थल व नभ में प्रदूषण फैलाता है। मौजूदा निपटान प्रक्रियाएं महंगी व पर्यावरण-प्रतिकूल हैं। ऐसे में नये विकल्प तलाशने चाहिए।

धरती पर निरंतर बढ़ता प्लास्टिक कचरा एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बनकर उभर रहा है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 94 लाख टन से लेकर 1.02 करोड़ टन तक प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है। धरती, समुद्र, पहाड़, नदियां -शायद ही कोई कोना प्लास्टिक कचरे की घुसपैठ से बचा हो! सड़कों, गलियों, नालियों में यत्र-तत्र फैंके गए प्लास्टिक के लिफाफ़े अक्सर भूखे जानवरों के गले में फंसकर उनकी मौत तक को न्योता दे सकते हैं। गत दिनों दैनिक ट्रिब्यून में ही प्रकाशित एक ख़बर के अनुसार, हरियाणा में क़रीब चार फुट लंबे कोबरा के पेट में काली पॉलीथिन फंसने से उसकी जान पर बन आई। हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) के चिकित्सकों ने क़रीब एक घंटे की सर्जरी करके इंसानी लापरवाही के शिकार निरीह जीव को 'प्लास्टिक आफत' से निजात दिलाई!

देश में 1 जुलाई, 2022 से लागू सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक के कटलरी-स्ट्रॉ, पतले प्लास्टिक सजावटी सामान तथा गुणवत्ता रहित प्लास्टिक लिफाफे प्रतिबंधित होने के बाबजूद ये आम प्रचलन में हैं। विशेषकर, घटिया मेटिरियल से निर्मित प्लास्टिक के लिफाफे आज भी देश के अधिकतर हिस्सों में देखे जा सकते हैं। सामान डालने के लिए समुचित व सर्वसुलभ विकल्प उपलब्धता न करा पाना इसमें मुख्य कारण है, जिसके चलते जुर्माने जैसी दंडात्मक कार्रवाई की कोशिश भी खटाई में पड़ती देखी गई।

विकास तथा आधुनिकीकरण ने यदि वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक के निर्माण तथा उपभोग में भारी वृद्धि की, तो इसमें मुख्य वज़ह इसकी बहुउपयोगिता, टिकाऊपन तथा अपेक्षाकृत कम लागत होना है। हालांकि, अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक बने रहने की यही विशेषता पर्यावरण की सेहत के लिहाज़ से हानिप्रद साबित होती है। प्लास्टिक के न सड़ने तथा वर्षों तक ज़मीन के अंदर कायम रहने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। प्लास्टिक बैग नालियां, सीवेज सिस्टम आदि ब्लॉक करके अस्वच्छता बढ़ाने के साथ बीमारियां फैलाने की वजह बनते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक के सूक्ष्म कण वायु, जल तथा भोजन के ज़रिए शरीर में प्रविष्ट होकर, मानव व अन्य जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाते हैं। प्लास्टिक से निकलने वाले रसायनों से हार्मोन असंतुलन, कैंसर जैसी समस्याएं पनप सकती हैं। इसे जलाने से उत्पन्न विषैली गैसें सांस संबंधी गंभीर बीमारियां उत्पन्न करती हैं।

प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक कचरे का दुनिया के समुद्रों तथा महासागरों में पहुंचना, समुद्री जीवन के लिए प्रतिकूलताएं लेकर आता है। आर्थिक गतिविधियों पर बोझ डालने वाला प्लास्टिक कचरा जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण बनता है। दरअसल,पर्यावरण व जैव विविधता के लिए गंभीर ख़तरा बन चुका प्लास्टिक कूड़ा वैज्ञानिक चमत्कार के बजाय पारिस्थितिक अभिशाप माना जाने लगा है।

प्लास्टिक कचरे का समुचित निस्तारण न हो पाना प्रमुख चुनौती है। देश में रोज़ाना निकलने वाले लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरे में से क़रीब 60 प्रतिशत कचरे का ही पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) हो पाता है, शेष हिस्सा पर्यावरण अथवा लैंडफिल में बना रहता है। इसका अनुचित निपटान पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता की हानि तथा पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण का व्यापक कारण बनता है। भस्मीकरण, लैंडफिलिंग जैसी उपलब्ध प्रक्रियाएं अस्थिर, महंगी व पर्यावरण के प्रतिकूल हैं। इसीलिए, अब जैव-अपघटनीय प्लास्टिक तथा वैकल्पिक निपटान विधियों जैसे विकल्पों पर बल दिया जा रहा है, विशेषकर, सूक्ष्म जीवों द्वारा कृत्रिम प्लास्टिक को बिना किसी हानिकारक प्रभाव के विघटित करने की क्षमता पर। नवीकरणीय संसाधनों से बने तथा जैव-अपघटनीय (बायोडिग्रेडेबल) बायोप्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण घटाकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है, किंतु भारी प्रगति के बावजूद स्केलेबिलिटी, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता तथा जीवनचक्र के अंत प्रबंधन जैसी कठिनाइयां कायम हैं, जिनके लिए अतिरिक्त अनुसंधान तथा नवाचार की जरूरत है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर बायोप्लास्टिक विकल्पों के विकास और कार्यान्वयन के लिए शिक्षाविदों, व्यवसायियों एवं सरकारों के बीच सहयोग अनिवार्य है।

प्लास्टिक उत्पादकों को जवाबदेह ठहराने के लिए मज़बूत नीतियां बनाने तथा लागू करने से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वस्तुस्थिति का जायज़ा लेते हुए वैकल्पिक प्रबंधन के उपाय ढूंढ़ना। इनके बग़ैर प्लास्टिक के उत्पादन व बिक्री पर पूर्णत: रोक लगाना संभव नहीं।

पृथ्वी हमारा घर है और इसे प्रदूषित होने से रोकना हम पृथ्वीवासियों की सर्वोपरि ज़िम्मेदारी। प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का सर्वोत्तम उपाय है, 'तीन आर सिद्धांत' (रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकल) का अनुपालन। कम्पोस्टेबल प्लास्टिक का उपयोग जैविक कचरे के साथ खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। आदर्श समाधान है, प्लास्टिक का प्रयोग घटाना। क्यों न अगली बार बाज़ार जाते समय कपड़े या जूट का बैग अपने साथ ले जाएं पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल की जगह धातु या कांच की बोतल का इस्तेमाल करें। व्यक्तिगत छोटे-छोटे सद्प्रयास ही सामूहिक स्तर पर अप्रत्याशित सफलता दिलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।

हवाई सर्वेक्षण में गड्ढाग्रस्त सड़कों की चमक

'माफ करना हुजूर! यह जो आप देख रहे हैं, ये शहर की सड़कों पर उभर आए गड्ढे हैं। इनमें बरसात का पानी भर गया है। पानी से भरे इन गड्ढों की सतह पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो आसमान से चमचमाते शीशे की माफिक दिखाई देते हैं।' नेताजी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। जब से नेता हुए हैं तभी से दिली तमन्ना थी कि बाढ़ आए और वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करें। और ऐसा हुआ। नेताई तमन्ना फौरन पूरी होने का राजनीतिक विधान है। हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए वह गदगद हो गए। चारों ओर पानी के हाहाकार से उनका मन हिलोरें लेने लगा। फौरन अपना मोबाइल निकाला और धड़ाधड़ रील पर रील खींचने लगे। जनता के दु:ख में दुखी होने का प्रमाण मोबाइल पर सहेजने लगे। हवाई सर्वेक्षण की उपलब्धि को सोशल मीडिया पर साझा करने की गरज से पायलट को दो-चार फेरे और लगाने का आदेश दिया।

सर्वेक्षण से लौटते हुए उनकी नजर फिर जमीन पर गई। यहां आसमान साफ था। सूरज चमक रहा था। नीचे कोई शहर दिखाई दे रहा था। शहर की सड़कों को देखकर वे चौंक गए। सड़कें चमचम कर रही थीं। विकास की ऐसी चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। नेताजी औचक अपने सहयोगी से बोले, 'अरे! आपने कभी इस शहर के बारे में बताया नहीं? यहां की सड़कें कितनी खूबसूरत हैं! सड़कों पर दूर-दूर तक छोटे-बड़े शीशे लगाए गए हैं। विकास का ऐसा मंजर अद्भुत है।'

सहयोगी हमेशा की तरह दांत निपोरने लगा। वाकई उससे गलती हो गई थी। नेताजी को बताया ही नहीं ऐसे विकसित सड़कों वाले शहर के बारे में। दरअसल उसे खुद इल्म नहीं था कि नेताजी के रहते कोई शहर इतना विकास कर सकता है। वे तो स्वयं के विकास में भरोसा रखते हैं। आश्चर्य! सड़कों पर शीशे बिछाए जाने की तकनीक विकसित हो गई। सहयोगी दूरबीन लेकर शहर की ओर ताकने लगा। हवाई सर्वेक्षण की गुदगुदी के बीच नेताजी की इच्छा जागी कि अब ऐसे शहर का सड़क-सर्वेक्षण कर वोट बटोरना चाहिए।

हेलीकॉप्टर का पायलट इसी शहर से आता था। वह सब बातें चुपचाप सुन रहा था। सो धीरे से मिनमिनाया, 'क्षमा करें आदरणीय! नीचे सड़कों पर यह जो चमकते हुए शीशे देख रहे हैं, दरअसल ये शीशे नहीं हैं।' वह संकोच में घिरा हुआ रुक गया। नेताजी अधीर हो उठे। जिज्ञासावश उसे डपट दिया, 'अबे! शीशे नहीं तो फिर क्या हैं?' पायलट दबी आवाज में बोला, 'माफ करना हुजूर! यह जो आप देख रहे हैं, ये शहर की सड़कों पर उभर आए गड्ढे हैं। इनमें बरसात का पानी भर गया है। पानी से भरे इन गड्ढों की सतह पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो आसमान से चमचमाते शीशे की माफिक दिखाई देते हैं।' नेताजी बगलें झांकने लगे। फौरन अपने मोबाइल का कैमरा बंद कर, रील डिलीट करने लगे।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई–दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

जिले में अब तक 488.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

दुर्ग। जिले में 1 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक 488.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा 620.0 मिमी तहसील पाटन में तथा न्यूनतम 318.4 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। तहसील दुर्ग में 549.9 मिमी, तहसील बोरी में 556.1 मिमी, तहसील भिलाई–3 में 488.2 मिमी और तहसील अहिवारा में 395.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 31 जुलाई 2026 को तहसील दुर्ग में 4.7 मिमी, तहसील धमधा में 3.2 मिमी, तहसील पाटन में 5.7 मिमी, तहसील बोरी में 6.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 5.7 मिमी और तहसील अहिवारा में 4.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों का निरंतर मिलाप कार्यक्रम 5 को

दुर्ग। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय दुर्ग के प्रांगण में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के प्रतिनिधियों के सहयोग से भूतपूर्व सैनिकों के लिए निरंतर मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला दुर्ग, बालोद, कबीरधाम एवं बेमेतरा में निवासरत केवल आर्मी के भूतपूर्व सैनिक शामिल हो सकेंगे। यह कार्यक्रम 5 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व सैनिक अपनी सेवा अभिलेखों, रिकॉर्ड संबंधी समस्याओं, पार्ट–टू आदेश, पेंशन अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे।

सांख्यिकी कार्यालय में पदस्थ झुमुक यादव हुए सेवानिवृत्त

दुर्ग। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय दुर्ग में पदस्थ झुमुक लाल यादव (भृत्य) 28 वर्षों की शासकीय सेवा पूर्ण करने के उपरांत आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में उपसंचालक श्रीमती कविता एंथोनी ने उन्हें पेंशन भुगतान आदेश प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके सुखद, स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

निःशुल्क कंप्यूटर व सॉफ्ट स्किल्स मार्गदर्शन शिविर 3 को

दुर्ग। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं में रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 3 अगस्त 2026 को एक दिवसीय मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पूर्वाह्न 11.00 बजे से आयोजित इस शिविर में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन द्वारा संचालित दो प्रमुख निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों 'सर्टिफाइड कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग असिस्टेंट' तथा 'सर्टिफाइड कोर्स इन आईटीईएस बीपीओ सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश' के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी। 2 से 3 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन स्मृति नगर भिलाई स्थित नायलिट स्टडी सेंटर में किया जाएगा।

बीएसपी में संयंत्र स्तरीय क्वालिटी सर्कल एवं 5-एस प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता 'गुणवत्ता-2026'

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल– भिलाई इस्पात संयंत्र के व्यवसायिक उत्कृष्टता विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास केन्द्र में 27 से 29 जुलाई 2025 तक 'गुणवत्ता–2026' संयंत्र स्तरीय क्वालिटी सर्कल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 'गुणवत्ता–2026' का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य में 31 जुलाई 2026 को संपन्न हुआ।

प्रतियोगिता में 48 टीमों ने पाँच अलग–अलग श्रेणियों — मैन्यूफैक्चरिंग स्ट्रीम, मैन्यूफैक्चरिंग सपोर्ट स्ट्रीम, प्योर सर्विसेज स्ट्रीम, लीन क्वालिटी सर्कल तथा 5–एस में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मकता और समस्या–समाधान की क्षमता का प्रदर्शन किया। मैन्यूफैक्चरिंग स्ट्रीम में टीम अनन्या (एसपी–3) ने प्रथम, टीम सार्थक (सीओ सीसीडी) ने द्वितीय और टीम प्रगति–पाथ (यूआरएम) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

मैन्यूफैक्चरिंग सपोर्ट स्ट्रीम में टीम प्रवाह (पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन) प्रथम, टीम उर्जा (यूआरएम) द्वितीय और टीम मुस्कान (एसएमएस–2) तृतीय रही। वहीं प्योर सर्विसेज स्ट्रीम में टीम स्पर्श (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ) ने प्रथम और टीम श्रम सारथी (मानव संसाधन) ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

लीन क्वालिटी सर्कल श्रेणी में टीम अभ्युदय (यूआरएम) प्रथम, टीम राफ्ट (ब्लास्ट फर्नेस–8) द्वितीय और टीम धैर्य (एसएमएस–3) तृतीय रही। साथ ही 5–एस श्रेणी में टीम जागृति (एस.एस शॉप) प्रथम, टीम विकास (आरईसीएल शॉप) द्वितीय और टीम 'जागरूक होता इंसान' (मार्स–1) तृतीय रही।

6 टीमों की विभागीय भागीदारी के लिए यूआरएम को ट्रॉफी प्रदान की गई। सभी विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार ने कहा कि संयंत्र में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में यह प्रतियोगिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बीएसपी में संविदा श्रमिकों के लिए समयबद्ध एवं पारदर्शी वेतन भुगतान की ठोस व्यवस्था

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल– भिलाई इस्पात संयंत्र ने संविदा श्रमिकों के हितों के संरक्षण तथा पारदर्शी, समयबद्ध एवं डिजिटल वेतन भुगतान व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ एस्क्रो आधारित डिजिटल वेतन भुगतान प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रिकॉर्ड ऑफम्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग संपन्न किया।

PUNJAB NATIONAL BANK
सेल SAIL
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
LG

इस संबंध में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (ऑटोमेशन एवं डिजिटलीकरण) रवि शंकर, महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन) जे. एन. ठाकुर, महाप्रबंधक (मानव संसाधनङ्कवर्क्स) संजय द्विवेदी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन–औद्योगिक संबंध एवं संविदा श्रम प्रकोष्ठ) राजीव कुमार, महाप्रबंधक (टाउनशिप) विकास चन्द्रा, महाप्रबंधक (सी एंड आईटी) सरबानी दास, महाप्रबंधक (मानव संसाधन – मिल्स, एम एंड एस) प्रताप शेखर नायक और महाप्रबंधक (मानव संसाधन – वेलफेयर) सुरजीत मलिक सहित मानव संसाधन एवं सी एंड आईटी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

पंजाब नेशनल बैंक की ओर से सर्किल हेड, रायपुर वी. के. शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (सीएससी) प्रवीण कुमार, मुख्य प्रबंधक, सिविक सेंटर शाखा अजीत साहू तथा बैंक के अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस अवसर पर अपने संबोधन में कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार ने कहा कि यह पहल भिलाई इस्पात संयंत्र एवं पंजाब नेशनल बैंक के मध्य सहयोग का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एस्क्रो आधारित डिजिटल वेतन भुगतान प्रणाली के क्रियान्वयन से संविदा श्रमिकों के वेतन भुगतान में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं विश्वसनीयता और अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने इस पहल को सफल स्वरूप देने में भिलाई इस्पात संयंत्र की टीम द्वारा किए गए सतत प्रयासों की सराहना करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया।

महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन) जे. एन. ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि यह व्यवस्था संविदा श्रमिकों के वेतन भुगतान से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि इससे वैधानिक प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन को भी मजबूती मिलेगी तथा श्रमिकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रदान किए जा रहे निरंतर सहयोग की सराहना की।

कार्यक्रम के दौरान दोनों संस्थानों ने एस्क्रो आधारित डिजिटल वेतन भुगतान प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु परस्पर सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक (मानव संसाधन–औद्योगिक संबंध एवं संविदा श्रम प्रकोष्ठ) राजीव कुमार द्वारा किया गया।

नगरीय क्षेत्रों में पट्टा, नवीनीकरण, व्यवस्थान के लिए कलेक्टर ने बनाई टीम

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन को गति देने के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्राधिकृत अधिकारियों, सहायक अधिकारियों एवं जांच दलों का गठन किया है। इस व्यवस्था के तहत नगरीय निकायों में नवीन पट्टा प्रदाय, पट्टों का नवीनीकरण, अवैध या अनियमित पट्टों का नियमितीकरण, कब्जा की अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन तथा धारणाधिकार परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु क्षेत्रवार अधिकारियों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

नगर पालिक निगम दुर्ग तथा नगर पालिक निगम भिलाई के जोन–3, 4 और 5 के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग महेश राजपूत को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

भिलाई निगम के जोन–1 और 2 के लिए डिप्टी कलेक्टर दुर्ग सोनाल डेविड को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है, जिसमें आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नामांकित अधिकारी सहायक अधिकारी होंगे।

नगर पालिक निगम भिलाई–चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई–3 प्रकाश सोनी को जिम्मेदारी दी गई है।

नगर पालिक निगम रिसाली और नगर पंचायत उतई क्षेत्र हेतु डिप्टी कलेक्टर दुर्ग प्रफुल्ल गुप्ता प्राधिकृत अधिकारी होंगे। नगर पंचायत धमधा के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा लवकेश ध्रुव को प्रभार सौंपा गया है।

नगर पालिका परिषद अमलेश्वर तथा नगर पंचायत पाटन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन उत्तम ध्रुव प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं नगर पालिका परिषद जामुल एवं अहिवारा क्षेत्र के लिए डिप्टी कलेक्टर दुर्ग प्रेमु साहू को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।

इन सभी प्राधिकृत अधिकारियों को दो दो सहायक दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन सभी प्रभार क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्रों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा हल्का पटवारी जांच अधिकारी और सहायक कर्मचारी के रूप में दल में शामिल रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

24 एमएलडी फिल्टर प्लांट की होगी सफाई 3 से 4 अगस्त तक नहीं आएगा नल से पानी

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग के 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट में जल शोधन व्यवस्था को और अधिक सुचारु एवं गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक 03 एवं 04 अगस्त 2026 से विशेष दो दिन सफाई अभियान चलाया जाएगा। यह कार्य लगातार दो दिनों तक संचालित होगा।

सफाई कार्य के दौरान शाम के समय जल उत्पादन प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए शाम की जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी, जबकि प्रातःकालीन जलापूर्ति पूर्ववत एवं सामान्य रूप से जारी रहेगी।

इस कार्य के कारण शंकर नगर, शक्ति नगर, पद्मनाभपुर, शनिचरी बाजार, हनुमान नगर, ट्रांसपोर्ट नगर एवं गिरधारी नगर क्षेत्र की ओवरहेड टंकियों से होने वाली शाम की जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है।

इन क्षेत्रों के नागरिकों से अनुरोध है कि वे आवश्यकतानुसार सुबह ही पेयजल का पर्याप्त भंडारण कर लें तथा जल का उपयोग संयमित एवं आवश्यकतानुसार करें।

नगर निगम द्वारा बताया गया है कि फिल्टर प्लांट की नियमित सफाई से जल की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ–साथ जलापूर्ति व्यवस्था अधिक प्रभावी एवं सुरक्षित होगी। सफाई कार्य पूर्ण होते ही जलापूर्ति पुनः सामान्य कर दी जाएगी।

नगर पालिक निगम, दुर्ग ने नागरिकों से इस आवश्यक रखरखाव कार्य में सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि असुविधा के लिए निगम को खेद है।

रिसाली में 1.65 करोड़ से चार वार्डों में होगा विकास

श्रीकंचनपथ समाचार

रिसाली। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा ने रिसाली के विकास कार्य के लिए शुक्रवार चार अलग–अलग वार्डों में भूमिपूजन किया। क्षेत्र में 1 करोड़ 65 लाख 94 हजार से सड़क, नाली, भवन और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास जनता के लिए होता है।

विधायक ललित चंद्राकर ने भूमिपूजन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है। विकास कार्य कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता। जनता की मांग पर ही योजनाएं तैयार कर उसे अमल पर लाया जाता है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता की मंशा अनुरूप कार्य करता है। यही कारण है कि वें लगातार निगम क्षेत्र के अलग–अलग वार्डों तक पहुंच रहे है और मांग अनुरूप भूमिपूजन कर रहे है। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि विकास कार्य में कभी पैसा बाधा नहीं बनेगा। इस अवसर पर महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि क्षेत्र के विकास में सभी का सहयोग आवश्यक है। रिसाली निगम गठन के बाद क्षेत्र में विकास हुआ है और आगे भी कार्य होते रहेंगे। विकास कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। भूमिपूजन कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू ने भी संबोधित किया।

वार्ड क्र. 32 नेवई भाठा में नाली, सीसी रोड व सौंदर्यीकरण के तीन कार्यों के लिए कुल 19.48 लाख शासन ने स्वीकृत की है। इसी तरह वार्ड क्र. 33 नेवई बस्ती पूर्व में 45 लाख 48 हजार की राशि से कुल दस कार्य, वार्ड क्र. 34 नेवई बस्ती पश्चिम में 29 लाख 45 हजार से चार कार्य और वार्ड क्र. 21 सूर्या नगर में 71 लाख 53 हजार की राशि से कुल सात विकास कार्य होंगे।

छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति को बढ़ावा देने आईआईटी में 'प्रातिज्ञ' आयोजित

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी का सांस्कृतिक कार्यक्रम 'प्रातिज्ञ', 30 जुलाई 2026 को आईआईटी भिलाई कैंपस के नालंदा लेक्चर हॉल में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 'सेंटर फॉर स्टडीज ऑन कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडीशन्स' (सीसीएलटी) की साझेदारी में आयोजित किया गया था।

सीसीएलटी, आईआईटी भिलाई का एक रिसर्च सेंटर है जो सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और टिकाऊ विकास के क्षेत्रों में सामाजिक रूप से असरदार रिसर्च पर काम करता है। 'प्रातिज्ञ' अकादमी का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक और लोक व आदिवासी कलाओं के जाने–माने कलाकार और विद्वान व्याख्यान–प्रदर्शन के ज़रिए अपने अनुभव साझा करते हैं।

इस कार्यक्रम में राज्य की शास्त्रीय, लोक और आदिवासी नृत्य शैलियों के तीन जाने–माने कलाकारों ने व्याख्यान–प्रदर्शन दिएरू रायगढ़ घराने के मशहूर कथक गुरु और पद्म श्री व संगीत नाटक अकादमी रत्न फेलोशिप पाने वाले रामलाल बारेठ; बैगा नृत्य गुरु और पद्म श्री व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह धुर्वे; और नाचा (लोक थिएटर) के कलाकार व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता काशीराम साहू। कार्यक्रम में पद्मश्री और बस्तर बैंड के संस्थापक अनूप रंजन पांडे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार विजेता धनीराम कड़ामिया भी मौजूद थे। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर प्रो. राजीव प्रकाश ने स्वागत भाषण दिया और कलाकारों का सम्मान किया।

अपने स्वागत भाषण में, प्रो. प्रकाश ने कहा कि 'प्रातिज्ञ' छत्तीसगढ़ की समृद्ध और विविध कलात्मक विरासत को बचाने और उसे आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों को कलाकारों से जोड़कर और इसे पाठ्यक्रम में शामिल करके समृद्ध संस्कृति और कला को बचाने और बढ़ावा देने की पहल कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 'प्रातिज्ञ' जैसे कार्यक्रम छात्रों को राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के बारे में और जानने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इन कलाओं को सीखने में उनकी रुचि जगाते हैं।

इस कार्यक्रम में गुरुओं और उनके शिष्यों के व्याख्यान–प्रदर्शन शामिल थे। पहले हिस्से में श्री रामलाल बारेठ के शिष्यों ने कथक की प्रस्तुति दी, जिसके बाद श्री बारेठ ने व्याख्यान–प्रदर्शन दिया। इसमें उन्होंने रायगढ़ बंदिश और तराना की बारीकियों और खासियतों के बारे में बताया।

छत्तीसगढ़ी बोली में श्री साहू की कॉमेडी स्केच की एकल प्रस्तुति ने 'नाचा' के हल्के–फुल्के लेकिन व्यंग्यात्मक अंदाज को पेश किया। श्री अर्जुन धुर्वे और उनके दल ने बैगा नृत्य का व्याख्यान–प्रदर्शन दिया। श्री धुर्वे ने बताया कि कैसे नृत्य और संगीत बैगा संस्कृति के रोजमर्रा के जीवन और रीति–रिवाजों का अहम हिस्सा हैं। इस प्रदर्शन में बैगा समुदाय के अलग–अलग समारोहों के दौरान किए जाने वाले नृत्य और गीत शामिल थे।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

दिव्यांगता को मात देकर चितुराम नाग बने आत्म-निर्भरता की मिसाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजना ने एक दिव्यांग युवक के जीवन को नई दिशा दी है। दंतेवाड़ा जिले के बचेली निवासी चितुराम नाग ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। चितुराम नाग ने वर्ष 2017 में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ वित्त एवं विकास निगम से 3.60 लाख रुपये का ऋृण प्राप्त किया था। उन्होंने इस राशि का उपयोग अपने रोजगार को मजबूत करने में किया और लगातार मेहनत करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने पूरे ऋण का समय सीमा के भीतर भुगतान कर दिया। अब उनका ऋण खाता पूरी तरह बंद हो चुका है। यह उपलब्धि उनके आत्मविश्वास, वित्तीय अनुशासन और स्वावलंबन का प्रमाण है।

नियमित यूडीआईडी शिविर से दिव्यांगजनों को मिल रही पहचान

रायपुर। प्रदेश में दिव्यांगजनों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरल, सुगम और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) अभियान महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आ रहा है। बलरामपुर जिले में जिला अस्पताल में प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे यूडीआईडी पंजीयन शिविरों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों सहित सभी पात्र दिव्यांगजनों को एकीकृत पहचान उपलब्ध कराई जा रही है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में इस सप्ताह 45 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम ने हितग्राहियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर यूडीआईडी पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण भी किया।

मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर तथा वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार बीजापुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। इसी क्रम में कलेक्टर विश्वदीप ने शुक्रवार को भोपालपटनम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का व्यापक दौरा कर राहत कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने सबसे पहले इंद्रावती नदी के तिमेड़ पुल का निरीक्षण कर जलस्तर और आवागमन की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद वे चंदनगिरी राहत शिविर पहुंचे और वहां रह रहे बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। राहत शिविर में भोजन, स्वच्छ पेयजल, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत शिविर में रह रहे सभी परिवारों को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुदृढ़ अधोसंरचना सरकार की प्राथमिकता- मंत्री टंक राम वर्मा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुदृढ़ अधोसंरचना (बुनियादी ढांचा) किसी भी राष्ट्र के विकास की मुख्य नींव हैं, जिन्हें सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर और आधुनिक माहौल मिलता है। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने शुक्रवार को वनांचल क्षेत्र नगरी को शिक्षा और आधारभूत विकास की बड़ी सौगात दी।

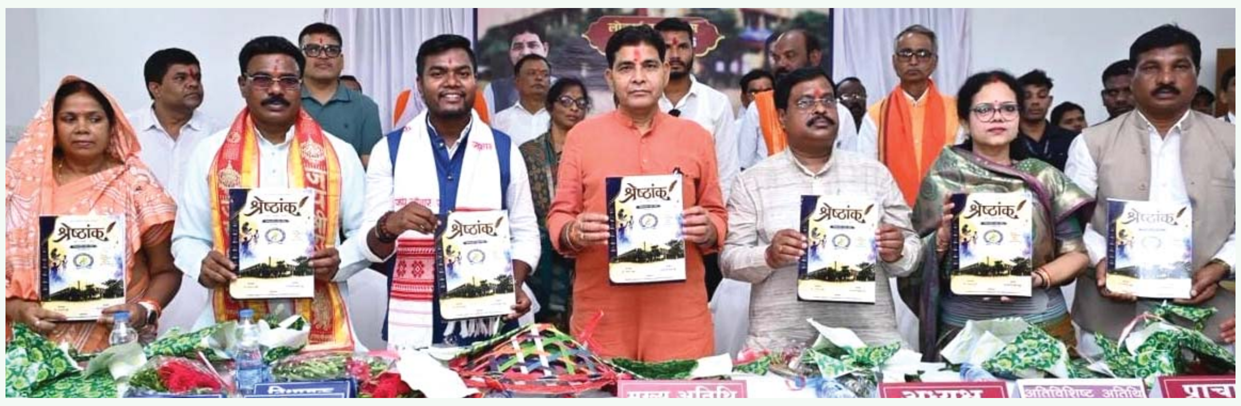

उन्होंने शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी में 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। इसके साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। ?इस दौरान मंत्री ने महाविद्यालय की वार्षिक साहित्यिक एवं शैक्षणिक पत्रिका 'श्रेष्ठांश' का विमोचन किया तथा परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के युवा ही राष्ट्र निर्माण का आधार हैं। बेहतर अधोसंरचना, आधुनिक संसाधन और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण से ही प्रदेश के भविष्य के जिम्मेदार नागरिक तैयार होंगे। नया अतिरिक्त कक्ष विद्यार्थियों के अध्ययन, शोध, सेमिनार और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा। ?उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और नवाचार का मंत्र देते हुए कहा कि निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।

मंत्री वर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प कर एक-एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण भावी पीढ़ियों के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है इस दौरान मंत्री श्री वर्मा ने महाविद्यालय भवन के साथ-साथ नगर पंचायत नगरी के लिए कई महत्वपूर्ण बुनियादी विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत नगरी अध्यक्ष, पूर्व विधायक पिंकी ध्रुव सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, महाविद्यालय परिवार, प्राध्यापकगण, प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं नागरिक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों को मिलेगी मजबूत डिजिटल पहचान, 2,305 नए मोबाइल टावरों के लिए मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से मांगी मंजूरी

प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर हुई विस्तृत चर्चा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में डिजिटल एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय, सीमावर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में निर्बाध मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 2,305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भौगोलिक दृष्टि से कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी आज केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता से इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तक सहज पहुंच मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के अनेक दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संचार नेटवर्क का विस्तार चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे क्षेत्रों में 2,305 नए मोबाइल टावरों की स्थापना डिजिटल समावेशन की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उन गांवों और बसाहटों तक भी विश्वसनीय मोबाइल एवं इंटरनेट नेटवर्क पहुंचेगा, जो अब तक पर्याप्त संचार सुविधाओं से वंचित रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित रहे एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर केंद्र सरकार तथा केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से बस्तर सहित कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आज शांति और विकास का नया वातावरण बन रहा है, वहां मजबूत संचार नेटवर्क विकास की गति को और तेज करेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद मजबूत होगा, आपातकालीन परिस्थितियों में संपर्क सुगम होगा और शासन की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लोगों को अपने गांव के निकट ही प्राप्त हो सकेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार स्वीकृत मोबाइल टावरों की स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। कुल 577 स्थानों में से अब तक 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किए जा चुके हैं। शेष 88 स्थानों के लिए भी आवश्यक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है और शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

डिजिटल कनेक्टिविटी बनेगी शिक्षा और स्वास्थ्य की नई ताकत

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल एवं इंटरनेट नेटवर्क के विस्तार का सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत होने से विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और डिजिटल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। इसी प्रकार टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से अधिक आसानी से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत नेटवर्क से बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी व्यवस्थाएं भी अधिक प्रभावी होंगी। ग्रामीण नागरिकों को विभिन्न प्रमाण-पत्रों, आवेदनों और अन्य ऑनलाइन शासकीय सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार डिजिटल कनेक्टिविटी शासन को नागरिकों के और करीब लाने का माध्यम बनेगी।

बाढ़ आपदा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क

महानदी तटवर्ती क्षेत्रों में तैयारियां तेज : ओपी चौधरी

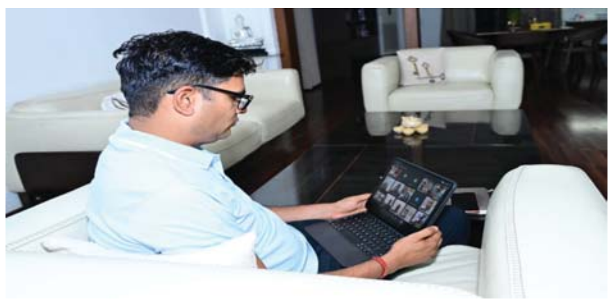

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महानदी के तटवर्ती क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने महानदी के जलस्तर, राहत एवं बचाव की तैयारियों तथा विभिन्न विभागों के समन्वय की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ जिले के महानदी तटवर्ती गांवों के साथ-साथ सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया अंचल और चंद्रपुर क्षेत्र के नदी किनारे बसे गांवों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार स्थिति पर पूरी गंभीरता और सतर्कता के साथ लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग और अधिकारी ओडिशा सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर महानदी के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हीराकुंड बांध के गेटों के संचालन को लेकर भी लगातार समन्वय किया जा रहा है, ताकि संभावित बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी नागरिकों को भी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित स्थानों पर जाने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अफ्वाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें, राहत एवं बचाव दलों को पूरी तरह तैयार रखें तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने का आग्रह किया। श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार, प्रशासन और जनता के सामूहिक सहयोग से किसी भी संभावित आपदा का प्रभावी ढंग से सामना किया जाएगा तथा जन-धन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

एक ही केंद्र पर मिली तीन अहम सुविधाएं, ग्रामीण की आसान हुई राह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित सेवा सेतु केंद्र सुशासन का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहे हैं। अब नागरिकों को आय, जाति, निवास सहित विभिन्न शासकीय प्रमाण-पत्रों और सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। एक ही स्थान पर मार्गदर्शन, आवेदन और निर्धारित समय-सीमा में समाधान मिलने से लोगों का समय और धन दोनों बच रहे हैं।

कोरबा जिले के भैंसमा क्षेत्र के ग्राम धौराभाठा निवासी चीन्हा राम इसका ताजा उदाहरण हैं। लंबे समय से जाति, निवास और आय प्रमाण-पत्र नहीं होने के कारण उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं और आवश्यक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र, भैंसमा में आवेदन किया, जहां कर्मचारियों ने पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन दिया और सभी औपचारिकताएं सरलता से पूरी कराईं।

निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन्हें तीनों आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिए गए। इससे न केवल उनकी परेशानी दूर हुई, बल्कि भविष्य में विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने का रास्ता भी आसान हो गया। चीन्हा राम ने बताया कि पहले ऐसे दस्तावेज बनवाने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। अब एक ही स्थान पर पूरी प्रक्रिया पूरी होने और समय पर प्रमाण-पत्र मिलने से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ''सेवा सेतु केंद्र'' ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहद उपयोगी पहल साबित हो रहे हैं। इससे शासन की सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आम नागरिकों तक पहुंच रही हैं।

भरपूर खाद-बीज, मजबूत योजनाएं और आधुनिक खेती से समृद्धि की राह पर छत्तीसगढ़ का किसान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि को अधिक लाभकारी, तकनीक आधारित और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आर्थिक सहायता, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा कृषि अधोसंरचना के विकास के माध्यम से प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी मंत्री रामविचार नेताम तथा कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागीय उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी मंत्री रामविचार नेताम तथा कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने आज संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागीय उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी।

मंत्री नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों की आय में वृद्धि, खेती की लागत में कमी तथा कृषि को आधुनिक और टिकाऊ बनाना है। राज्य में कृषि एवं उससे जुड़े सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं।

यूरिया का लक्ष्य से अधिक 102 प्रतिशत भंडारण किया गया है, जबकि डीएपी, एनपीके, एमओपी एवं एसएसपी सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। विभाग द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी तथा अवैध भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 30 जुलाई तक 5,466 निरीक्षण किए गए, जिनमें अनेक मामलों में एफ्आईआर, लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण तथा उर्वरक जब्ती जैसी कार्रवाई की गई। प्रदेश में खरीफ2026 के लिए लगभग 4.95 लाख क्विंटल बीज की मांग के विरुद्ध 4.85 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का भंडारण किया गया है, जो लगभग 98 प्रतिशत उपलब्धता को दर्शाता है।

प्रदेश में पर्याप्त खाद और बीज की उपलब्धता

प्रेसवार्ता में कृषि उत्पादन आयुक्त परदेशी ने बताया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए अप्रैल से सितंबर तक 15.55 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध 30 जुलाई 2026 तक 15.16 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का लगभग 98 प्रतिशत है। किसानों द्वारा अब तक 10.23 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का उठाव किया जा चुका है तथा लगभग 4.93 लाख मीट्रिक टन उर्वरक शेष उपलब्ध है।

डिजिटल इंडिया ने भारत को विश्व में नई पहचान दिलाई, सीएससी डिजिटल क्रांति के वास्तविक सूत्रधार : वित्त मंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर में कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा आयोजित '17 **Years of Progress with Purpose**' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीएससी संचालकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा डिजिटल इंडिया अभियान को जन-जन तक पहुँचाने में उनके योगदान की सराहना की।

YEARS OF
CSC
Programme Highlightes
Shri O.P. Choudhary Ji
17 YEARS OF
CSC DIWAS 2026
WELCOMES ALL PARTICIPANTS

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई है। आज भारत डिजिटल लेन-देन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। उन्होंने प्रदेश के 38 हजार पंजीकृत सीएससी संचालकों और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ नागरिकों को सरकारी सेवाएँ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएससी ने वास्तविक अर्थों में 'सिंगल विंडो सिस्टम' को चरितार्थ किया है, जहाँ एक ही स्थान पर राजस्व, श्रम, बिजली, आयुष्मान, बैंकिंग सहित अनेक सेवाएँ आम नागरिकों को मिल रही हैं।

मंत्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, तब कई लोगों ने इसकी सफ्लता पर सवाल उठाए थे।

लेकिन आज भारत डिजिटल भुगतान, यूपीआई और जनसेवा के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। गाँवों तक डिजिटल सेवाओं की पहुँच ने डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाया है। इसी से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने 'छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047' तैयार किया है, जिससे विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है। आज महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजनाओं की राशि बिना किसी कटौती के सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुँच रही है। इसमें सीएससी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार का मजबूत माध्यम बन रहे हैं। भविष्य में अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को सीएससी से जोड़ने तथा विकसित भारत 'जी-राम-जी' अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायतों में आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में भी सरकार कार्य करेगी।

मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार सीएससी नेटवर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों की नई सेवाओं को सीएससी से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में इनके लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को और अधिक सुविधाएँ एक ही स्थान पर मिल सकें।

कार्यक्रम के अंत में वित्त मंत्री ने सीएससी की पूरी टीम को सफ्ल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा सीएससी संचालकों के साथ खड़ी रहेगी और जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बैंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, कैम्प 2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

रानी पिंक सूट में शहनाज ने ढाया कहर, वायरल एथनिक फोटोशूट ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री की चहेती अदाकारा शहनाज गिल अपने स्टाइल स्टेटमेंट और गजब के ट्रांसफॉर्मेशन से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नया एथनिक फोटोशूट पोस्ट किया है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गया है।

इस लेटेस्ट फोटोशूट में शहनाज ने गहरे रानी पिंक कलर का बेहद खूबसूरत एथनिक सूट कैरी किया है। उनके इस आउटफिट को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। कुर्ती के योक पर गोल्डन थ्रेडवर्क, बारीक गोटा-पत्ती और जटिल जरदोजी वर्क के साथ-साथ शानदार मिरर और सेक्विन वर्क किया गया है।

कुर्ती के डीप-नेकलाइन और स्लीव्स के किनारों पर लगे लटकन-मोती इस ड्रेस को एक रॉयल और हेरिटेज लुक दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने मैचिंग एम्ब्रॉयडरी वाली स्ट्रेट-फिट एंकल लेंथ पैंट और नेट का एक खूबसूरत शीर दुपट्टा पेयर किया है, जो उनके पूरे लुक में एलिगेंस का तड़का लगा रहा है।

शहनाज गिल अपने ने मेकअप को बेहद सिंपल और सटल रखा है। उन्होंने लाउड कलर्स को छोड़कर न्यूड-ग्लॉसी लिप्स, न्यूड आईशैडो, मस्कारा से सजी पलकें और हल्का सा ब्लश ऑन चुना है, जो उनके नेचुरल फीचर्स को बखूबी उभार रहा है।

हेयरस्टाइल की बात करें तो शहनाज ने अपने सिग्नेचर स्टाइल को अपनाते हुए बालों को मिडल-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेवी लुक दिया है। उनके खुले काले बाल कंधों पर लहराते हुए उनके चेहरे के कट को बेहद खूबसूरती से फ्रेम कर रहे हैं।

शहनाज गिल का यह फोटोशूट किसी लग्जरियस इनडोर स्टूडियो का लग रहा है, जहां वह एक आलीशान विंटेज आर्मचेयर पर बैठकर बेहद दिलकश अंदाज में पोज दे रही हैं। तस्वीरों में शहनाज का आत्मविश्वास और उनका सेक्सी पोस्चर साफ झलक रहा है।

कभी वह चेयर पर रॉयल अंदाज में पीछे की ओर झुककर कैमरे में इंटेंस लुक दे रही हैं, तो कभी अपनी थिक-बॉर्डर वाली पैंट और गोल्डन हील्स को फ्लॉन्ट करते हुए फ्रंट पोज दे रही हैं। एक तस्वीर में वह अपने सिर को हाथों से थामे हुए गहराई से सोचती नजर आ रही हैं, जो उनके फैंस को काफी आकर्षित कर रहा है।

शहनाज के चेहरे का ग्लो और उनके सिजलिंग फेशियल एक्सप्रेशंस इस पारंपरिक आउटफिट में भी बोल्डनेस और ग्लैमर का परफेक्ट फ्यूजन पेश कर रहे हैं। शहनाज की इन तस्वीरों पर कमेंट बॉक्स में फैंस बॉम्बशेल, रॉयल क्वीन और ब्यूटी इन पिंक जैसे कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में इस पोस्ट पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं।

ऋचा चड्ढा का ओटीटी के बाद अब यूट्यूब पर जलवा मुसाफिरी के साथ नया सफर शुरू

गर्ल्स विल बी गर्ल्स से बतौर निर्माता वाहवाही बटोरने के बाद अभिनेत्री ऋचा चड्ढा अब अपने एक नए प्रोजेक्ट के साथ तैयार हैं। ऋचा अपने प्रोडक्शन हाउस पुशिंग बटन स्टूडियोज के तहत एक नई नॉन-फिक्शन सीरीज मुसाफिरी लेकर आ रही हैं। सफर, जीवन के अनुभवों और अनकही कहानियों को समेटने वाली उनकी ये सीरीज इसी साल अगस्त में उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज की जाएगी।

एक ट्रैवल सीरीज के रूप में तैयार की गई मुसाफिरी में आपको यात्रा, संस्कृति और दिलचस्प बातचीत का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

इसमें ऋचा खुद अलग-अलग खूबसूरत जगहों की सैर करती नजर आएंगी, जहां वो वहां की कहानियों, इतिहास, परंपराओं और स्थानीय लोगों की जिंदगी को करीब से तलाशेंगी। मुसाफिरी का मकसद दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ नई जानकारी देना और एक उत्सुक मुसाफिर की नजरों से दुनिया को देखने का एक नया नजरिया पेश करना है।

अपनी सीरीज पर ऋचा ने कहा, सफर ने मुझे हमेशा रुकने, चीजों को गहराई से देखने और सीखने का मौका दिया है। मुसाफिरी के जरिए मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी, जो सिर्फ जगहों की सूची पर टिक लगाने तक सीमित न रहे। हर जगह की अपनी एक लय, इतिहास और लोग होते हैं, जिन्हें अक्सर आम ट्रैवल कंटेंट में उतनी जगह नहीं मिल पाती। ये सीरीज इन्हीं परतों को धीरे-धीरे महसूस करने और अनुभव करने के बारे में है। ऋचा बोलीं, उम्मीद है कि दर्शक इसे देखकर न केवल अपनी अगली ट्रिप के नए विचार लेकर जाएंगे, बल्कि उन खूबसूरत जगहों और वहां रहने वाले लोगों के प्रति उनका नजरिया भी बदलेगा।

सीरीज और बतौर निर्माता अपने मकसद पर बात कर ऋचा ने कहा, मुझे ऐसी कहानियों को बढ़ावा देना पसंद है, जो अर्थपूर्ण हों, और मुसाफिरी मेरी इसी सोच को दर्शाती है। मैं इस खास सफर को आप सभी के साथ साझा करने के लिए बेहद उत्सुक हूं। बता दें कि प्रीति पाणिग्रही और कानी कुसरुति अभिनीत फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसने उस साल का इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवॉर्ड भी अपने नाम किया था।

ये फिल्म इस समय अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री में इस साल 18 साल पूरे कर रहीं ऋचा चड्ढा को आखिरी बार संजय लीला भंसाली की नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज हीरामंडी में देखा गया था।

प्रीति मेरे करियर का सबसे यादगार किरदार

इंटीमेट सीन पर बोलीं 'मुसाफिर कैफ' फेम महिमा मकवाना

कुछ किरदार सिर्फ पर्दे पर नहीं रहते, कलाकार के भीतर भी बस जाते हैं। अभिनेत्री महिमा मकवाना के लिए 'मुसाफिर कैफे' की 'प्रीति' ऐसा ही किरदार रही। महिमा कहती हैं कि इस रोल ने उन्हें खुद को स्वीकार करना और खुद से प्यार करना सिखाया। उन्होंने अपने करियर, इंटीमेट सीन्स, टीवी से फिल्मों तक के सफर और मसूरी में अपने डॉग के नाम पर 'परिंदा कैफे' खोलने के सपने पर खुलकर बात की।

स्क्रिप्ट पढ़ते ही प्रीति के किरदार से हो गया था प्यार

महिमा कहती हैं कि 'मुसाफिर कैफे' की स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्हें लगा कि वह प्रीति का किरदार निभाना चाहती हैं। 'जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, तभी मुझे लगा कि मुझे प्रीति ही बनना है। वह बहुत एस्पिरेशनल है। सोलो ट्रैवल करती है, अपने आसपास के लोगों को अपनापन महसूस कराती है, बहुत अच्छी लिस्नर है और बेहद इमोशनली इंटेलिजेंट है। अगर मुझे कभी असल जिंदगी में प्रीति मिले, तो मैं उससे दोस्ती जरूर करना चाहूंगी। वह ऐसी इंसान है, जो आपको रास्ता भी दिखाएगी और यह भी महसूस कराएगी कि आप अकेले नहीं हैं।'

इस किरदार ने मुझे खुद को स्वीकार करना और खुद से प्यार करना सिखाया

महिमा के लिए 'प्रीति' सिर्फ एक रोल नहीं रही। वह मानती हैं कि इस किरदार ने उनकी निजी जिंदगी पर भी असर डाला 'मुझे पहले खुद को स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता था। आसपास का शोर और लोगों की बातें कहीं न कहीं असर करती थीं। लेकिन प्रीति ने मुझे खुद को एक्सेप्ट करना सिखाया। उसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। मुझे एहसास हुआ कि जब तक आप खुद को आजादी नहीं देंगे... तब तक आप अपने आसपास के लोगों को भी आजादी महसूस नहीं करा पाएंगे। मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। मैं यह सिर्फ फिल्म प्रमोट करने के लिए नहीं कह रही हूं। मुझे सच में लगता है कि प्रीति मेरे करियर का सबसे यादगार किरदार रहेगी।' इस सीरीज की शूटिंग के दौरान उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया और धीरे-धीरे इसका असर अपनी जिंदगी में महसूस किया 'मैं यह नहीं कहूंगी कि मेडिटेशन ने मेरे जीवन का शोर पूरी तरह खत्म कर दिया, लेकिन उसने उसे काफी कम जरूर कर दिया। अब मैं खुद के पास जल्दी लौट पाती हूं।'

एक जैसे किरदार नहीं करना चाहती, अच्छे काम को देती हूं प्राथमिकता

करियर के फैसलों को लेकर भी महिमा जल्दबाजी में यकीन नहीं रखतीं 'बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होतीं। लेकिन मेरे फैसले हमेशा सोच-समझकर होते हैं। आखिर में मैं अपने इंस्टिंक्ट की सुनती हूं। मेरी क्लैरिटी बस इतनी है कि मुझे अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करना है। प्लेटफॉर्म मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर दर्शक आपसे जुड़ जाते हैं, तो वही सबसे बड़ी बात है।

सीरीज 'शो टाइम' के बाद मेरे पास कई एक जैसे ऑफर आए, लेकिन मैं खुद को दोहराना नहीं चाहती थी। मैं ऐसे किरदार करना चाहती हूं, जिनमें कुछ नया हो और कुछ मीनिंग हो। जब तक मैं खुद किसी किरदार पर भरोसा नहीं करूंगी, उसे ईमानदारी से निभा भी नहीं पाऊंगी।'

फिल्म दालिंब का टीजर जारी, जितेंद्र कुमार ने दिखाया अब तक का सबसे अलग रूप

पंचायत सीरीज से लोकप्रिय हुए अभिनेता जितेंद्र कुमार अपनी नई फिल्म दालिंब लेकर आ रहे हैं। इस साल मार्च में निर्माताओं ने उनकी पहली झलक को पोस्टर के साथ जारी किया था। अब आधिकारिक टीजर सामने आया है। जी5 और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनी ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें जितेंद्र का लुक सबसे अलग होने वाला है। फिल्म की कहानी और निर्देशन की जिम्मेदारी प्रिया एवेन ने संभाली है, जबकि वरद भटनागर ने लिखे हैं।

टीजर में जितेंद्र बिल्कुल अलग, डार्क और रहस्यमयी अवतार में नजर आए हैं। उनका चेहरा पारंपरिक लोककलाकार की तरह रंगा दिखाया गया है।

निर्माताओं ने कैप्शन दिया, एक बच्चा लापता हो जाता है। एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। दोनों को ढूंढने की दौड़ शुरू होती है।

मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित ये फिल्म क्राइम, अपराधबोध, भावनात्मक पल और रहस्यमयी मिथक होने का संकेत देती है।

इसका प्रीमियर जी5 पर होगा, लेकिन रिलीज तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है।

HINDI ZEE5 ORIGINAL
DALIMB
OFFICIAL TEASER
हिंदी Z5

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है नींबू, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे

नींबू एक ऐसा फल है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। इसमें विटामिन-सी, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। नींबू का पानी पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है और यह पाचन को भी बेहतर बनाता है। आइए जानते हैं कि नींबू का सेवन कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में सहायक

नींबू विटामिन-सी का अच्छा स्रोत है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है।

नियमित रूप से नींबू पानी पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलती है।

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण भी शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे हम बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा के भोजन में नींबू को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

पाचन के लिए है लाभकारी

नींबू का सेवन पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह पेट की अम्लता को संतुलित करता है और भोजन को पचाने में मदद करता है।

इसके अलावा यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक है। नींबू में मौजूद फाइबर पेट की सफाई करता है और इसे स्वस्थ रखता है।

नियमित रूप से नींबू पानी पीने से पेट की समस्याओं से बचाव होता है और पाचन बेहतर होता है।

वजन कम करने में है मददगार

वजन कम करने के लिए भी नींबू बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद पेक्टिन फाइबर भूख को कम करता है, जिससे आप कम खाते हैं और वजन घटाने में मदद मिलती है।

इसके अलावा नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी सहायक होते हैं।

इसलिए अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आहार में नींबू को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

त्वचा की देखभाल करने वाला है बेहतरीन

नींबू त्वचा की देखभाल करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एसिड त्वचा की गंदगी हटाता है और इसे साफ-सुथरा बनाता है। नींबू का रस मुंहासों के निशान हटाने में भी कारगर होता है।

इसके अलावा यह त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए नींबू को अपने त्वचा देखभाल के तरीके में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अन्य फायदे भी हैं जो त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं।

हृदय के लिए है फायदेमंद

हृदय रोगों से बचाव करने में भी नींबू बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद खास तत्व हृदय रोगों से बचाव करने में सहायक होते हैं।

इसके अलावा नींबू में पोटेशियम मौजूद होता है, जो रक्तचाप को संतुलित रखता है और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।

इस प्रकार नींबू कई तरीकों से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इसे अपने रोजमर्रा के भोजन में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

सहकारिता के माध्यम से कृषि में तकनीकी क्रांतिः धमतरी बना देश का पहला जिला, 10 प्राथमिक कृषि साख समितियों से शुरू हुई ड्रोन सेवा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले ने कृषि के आधुनिकीकरण और सहकारिता आधारित नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान स्थापित की है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करते हुए धमतरी देश का पहला जिला बन गया है, जहाँ 10 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को संगठित रूप से ड्रोन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

इस अभिनव पहल के लिए रायपुर में आयोजित सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस समारोह में जिले को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने जिला सहकारिता विभाग के उपायुक्त प्रदीप ठाकुर को यह सम्मान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता संस्थाओं के माध्यम से आधुनिक तकनीक को किसानों तक पहुँचाने की यह पहल कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी साबित होगी और अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।

कलेक्ट्रेट परिसर धमतरी में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए ड्रोन तकनीक का विशेष प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कृषि विशेषज्ञों ने ड्रोन आधारित फसल प्रबंधन, कीटनाशकों एवं नैनो उर्वरकों के वैज्ञानिक छिड़काव, कम समय में अधिक क्षेत्र में कार्य, श्रम लागत में कमी, संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता से अवगत कराया। प्रशिक्षण के बाद लोहरसी, दोनर, खरेंगा, अछोटा, बोड़रा, भोथीडीह, करेली, कुण्डेल, गाड़ाडीह एवं जुगदेही की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों ने किसानों को किराये पर ड्रोन सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इससे किसान आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कम लागत में अधिक प्रभावी एवं वैज्ञानिक खेती कर सकेंगे।

इस पहल का शुभारंभ 23 जुलाई 2026 को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित लोहरसी से सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किया था। उन्होंने किसानों से नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा था कि ड्रोन आधारित कृषि से खेती अधिक वैज्ञानिक, सुरक्षित और लाभकारी बनेगी। इससे उर्वरकों एवं कीटनाशकों का सटीक उपयोग होगा, उत्पादन लागत घटेगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी।

उल्लेखनीय है कि धमतरी की इस अभिनव पहल को इससे पूर्व कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी सराहना मिल चुकी है, जहाँ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए ड्रोन सेवा के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया था। धमतरी का यह मॉडल सहकारिता, नवाचार और आधुनिक तकनीक के प्रभावी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है।

खास-खबर

जनसेवा और डिजिटल सशक्तिकरण से मिली राज्यस्तरीय पहचान

रायपुर। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाला सुकमा जिला आज विकास और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव में कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों की अहम भूमिका रही है। छिंदगढ़ के सीएससी संचालक चंद्रशेखर साहू ने अपनी मेहनत और समर्पण से ग्रामीणों तक सरकारी योजनाएं और डिजिटल सेवाएं पहुंचाई हैं। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। पिछले 15 वर्षों से चंद्रशेखर साहू लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के बैंक मित्र (बीसी) के रूप में उन्होंने अब तक 50 हजार से अधिक बैंक खाते खोले हैं। यह उपलब्धि ग्रामीणों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वे ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ बीमा, आधार सेवाएं, किसान पंजीयन, श्रमिक पंजीयन, महतारी वंदन योजना और श्रम योगी मानधन योजना जैसी कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

कुक्कुट पालन से ग्रामीण परिवारों को मिली नई आजीविका

रायपुर। सुकमा जिले में ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशानुसार और पशुधन विकास विभाग के उपसंचालक डॉ. संदीप इंदुरकर के नेतृत्व में सुकमा विकासखंड के कई गांवों में 50 हितग्राहियों को निःशुल्क कुक्कुट इकाइयों का वितरण किया गया। इस योजना के तहत गीदम नाला, नींबूपदर, मुलागुडा, भेलवापाल और झापरा गांव के हितग्राहियों को प्रत्येक कुक्कुट इकाई में 45 चूजे और 10 किलोग्राम दाना उपलब्ध कराया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को कुक्कुट पालन से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। कुक्कुट इकाइयों का वितरण महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों की उपस्थिति में पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से किया गया।

बस्तर के प्रतिनिधियों ने देखा राष्ट्रपति भवन, संस्कृति का हुआ सम्मान

महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आत्मीय स्वागत से बस्तर का प्रतिनिधिमंडल हुआ अभिभूत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राष्ट्रपति भवन में बस्तर के प्रतिनिधिमंडल के लिए एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक क्षण साकार हुआ। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर से पहुंचे परगना मांझियों, चालकियों, बस्तर पंडुम के जनजातीय कलाकारों तथा समाज प्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने सभी अतिथियों का शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मान किया और बस्तर की समृद्ध जनजातीय परंपरा एवं संस्कृति के प्रति अपना विशेष स्नेह व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल के लिए सबसे भावुक और प्रेरणादायी क्षण उस समय आया, जब राष्ट्रपति महोदया ने एक आत्मीय मेजबान की भूमिका निभाते हुए स्वयं अपने हाथों से सभी अतिथियों को भोजन परोसा। राष्ट्रपति भवन में आत्मीयता और अपनत्व से भरे इस दृश्य ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को भावविभोर कर दिया। बस्तर से आए जनजातीय प्रतिनिधियों ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। इस अवसर पर एक और ऐतिहासिक पल तब आया, जब बस्तर पंडुम के विजेता कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन परिसर में अपनी पारंपरिक लोकगीत और लोकनृत्य की प्रस्तुति दी।

गढ़िया-लोहंडीगुड़ा परगना के मांझी बलराम कश्यप ने राष्ट्रपति महोदया को बताया कि पहले बस्तर के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उन्होंने मांझी समाज की ओर से राष्ट्रपति महोदया को विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरा और मुरिया दरबार में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। जिसे राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सहृदय स्वीकार भी किया। बीजापुर के मिरतुर परगना के चालकी भरत कश्यप ने बताया कि अब बच्चे बिना किसी भय के विद्यालय जा रहे हैं। गांवों में सड़कें बन रही हैं, दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदलते बस्तर में लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दंतेवाड़ा की बस्तर पंडुम विजेता गौर नृत्यांगना लक्ष्मी सोढ़ी ने राष्ट्रपति महोदया से कहा कि जिस बस्तर पंडुम की शुरुआत आपने की थी, उसी प्रतियोगिता की विजेता के रूप में राष्ट्रपति भवन पहुंचना उनके लिए गर्व और सम्मान का विषय है।

उन्होंने कहा कि आज बस्तर में शांति का वातावरण है और लोग मेला, जात्रा एवं मड़ई जैसे पारंपरिक आयोजनों को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के साथ राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

पहली बार दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का किया भ्रमण

बस्तर के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन का विस्तृत भ्रमण कर उसके गौरवशाली इतिहास और विरासत की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और अमर जवान ज्योति का भी अवलोकन किया। बस्तर के लोगों को राजधानी में देख सभी चकित नजरों से उन्हें देख रहे थे, सभी उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। इंडिया गेट के सामने सभी ने मिलकर 'ऐसा जादू है मेरे बस्तर में' और अन्य हल्बी-गोंडी गानों पर सभी के साथ सुर में सुर मिला कर आनंद लिया। राजधानी दिल्ली का यह अनुभव विशेष रूप से उन युवाओं के लिए यादगार रहा, जो पहली बार अपने गाँव और बस्तर से बाहर निकल कर देश की राजधानी पहुंचे हैं।

बस्तर की कला अब विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाएगी

राष्ट्रपति महोदया से बात करते हुए कांकेर के पद्म सम्मान से अलंकृत काष्ठ कलाकार अजय मंडावी ने कहा कि बस्तर की कला और संस्कृति विश्व में अद्वितीय है। लंबे समय तक भय और असुरक्षा के वातावरण के कारण इस विरासत को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि अब सुरक्षा बलों के साहस और सरकार के प्रयासों से बस्तर में शांति का वातावरण स्थापित हुआ है, जिससे कलाकारों को अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रखने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में बस्तर की कला वैश्विक पहचान बनाएगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने टेंट एंड डेकोर एक्सपो का किया शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के लाभांडी में छत्तीसगढ़ टेंट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीजी टेंट एंड डेकोर एक्सपो-2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक्सपो का अवलोकन कर टेंट एवं डेकोरेशन से जुड़े आधुनिक उत्पादों, आकर्षक डिज़ाइनों और नई तकनीकों की सराहना की। एक्सपो के शुभारंभ के मौके पर विधायक मोतीलाल साहू, टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा देशभर से आए टेंट व्यवसायी एवं इससे जुड़े लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टेंट व्यवसाय आज तेजी से विकसित होकर एक सशक्त उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है। नई थीम और लगातार हो रहे नवाचार इस क्षेत्र को नई पहचान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम समय में किसी भी स्थान का स्वरूप बदल देना टेंट व्यवसायियों की रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उप मुख्यमंत्री साव ने एक्सपो की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन कई शहरों के व्यवसायियों को एक मंच पर लाकर अनुभव साझा करने और व्यापार के नए अवसर तलाशने का अवसर देते हैं। यह एक्सपो टेंट उद्योग को बढ़ाने के साथ ही राज्य की आर्थिक गतिविधियों को और गति प्रदान करेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ टेंट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन को एक्सपों के आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।

जनता की सेहत से कोई समझौता नहींः मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, उपचार व्यवस्था, स्वच्छता तथा अस्पताल संचालन की स्थिति का जायजा लिया।

मंत्री राजवाड़े ने ओपीडी, वार्ड, प्रसूति कक्ष, दवा वितरण केंद्र, पेयजल व्यवस्था एवं अस्पताल परिसर की साफ-सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से चर्चा कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में पाई गई कमियों को तत्काल दूर किया जाए तथा मरीजों को समय पर उपचार, आवश्यक दवाएं एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, दवाओं का पर्याप्त भंडारण बनाए रखने तथा चिकित्सा उपकरणों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं को और प्रभावी बनाएं : डॉ. ममता साहू

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने आज धमतरी स्थित 'सखी वन स्टॉप सेंटर' का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में पीड़ित महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा वहां के समस्त पंजियों (रजिस्ट्रों) एवं पत्रावलियों की बारीकी से जांच की।

अध्यक्ष डॉ. साहू ने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन पूर्ण निष्ठा के साथ 24म7 (सातों दिन, 24 घंटे) सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी समय सहायता के लिए पहुंचने वाली पीड़ित महिला (आवेदिका) को किसी प्रकार की असुविधा या विलंब का सामना न करना पड़े।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने सखी सेंटर की योजनाओं और हेल्पलाइन की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रमुख स्थानों पर सूचनात्मक डिस्प्ले व होर्डिंग्स लगाने,बढ़ते साइबर अपराधों से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस विभाग के उप पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित कर विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन करने तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु जिले के माननीय न्यायाधीशों एवं शासकीय अधिवक्ताओं को आमंत्रित कर लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंने केंद्र में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति, उनके कार्य-विभाजन और केंद्र में आने वाले प्रकरणों के त्वरित निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक सुरक्षित संबल है। यहां आने वाली हर पीड़िता को समय पर न्याय, परामर्श और आश्रय मिलना हमारी पहली प्राथमिकता है।? इस दौरान राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव, आयोग के अधिकारी-कर्मचारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के स्थानीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर कावड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, विश्राम और सेवा की व्यवस्था

सावन में शिवभक्तों के लिए अमरकंटक में भक्ति और सेवा का संगम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पवित्र सावन माह के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा की पहल पर अमरकंटक स्थित मृत्युंजय आश्रम में कबीरधाम जिले सहित आसपास के कावड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है। सावन के पहले ही दिन 500 कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं ने मृत्युंजय आश्रम में प्रसादी ग्रहण किया। यह सेवा पूरे सावन माह तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सुबह की चाय और नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का निःशुल्क सात्विक भोजन, विश्राम स्थल, पेयजल, स्वच्छ शौचालय एवं प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

सेवा का संचालन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जो कावड़ यात्रियों का पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत एवं सेवा कर रही है। समिति के सदस्य लगातार यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सावन माह भगवान शिव की आराधना का महीना है और शिवभक्तों की सेवा करना वास्तव में शिव सेवा के समान है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा कठिन होती है और हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को इस यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपनी भक्ति पूर्ण कर सकें।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष लगभग 80 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने इस सेवा का लाभ लिया था और इस वर्ष भी बड़ी संख्या में कावड़ यात्री अमरकंटक पहुँच रहे हैं। लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सेवा केंद्र की व्यवस्थाओं का विस्तार भी किया गया है, ताकि किसी भी भक्त को असुविधा न हो। मृत्युंजय आश्रम स्थित यह सेवा केंद्र ना केवल भक्ति, बल्कि समाज सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदना का एक अनूठा उदाहरण बन चुका है। श्रद्धालु न केवल भगवान भोलेनाथ के दर्शन का लाभ ले रहे हैं, बल्कि सहजता, स्नेह और सहयोग का अनुभव भी कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से खुड़िया और लमनी में लगभग 20-20 लाख रुपए की लागत से कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षित पड़ाव के रूप में आधुनिक प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया है। सावन माह के दौरान कांवड़ियों की सुविधा और आपातकालीन चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए पूरे श्रावण मास तक एक एंबुलेंस की विशेष व्यवस्था भी की गई है।

श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, हर चेहरे पर दिखा संतोष का भाव

कबीरधाम से आए सैकड़ों श्रद्धालु जैसे ही मृत्युंजय आश्रम पहुँचे, वहाँ सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हर भक्त के चेहरे पर संतोष, श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव झलक रहा था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सहयोग से यह केंद्र एक भक्ति तीर्थ में तब्दील हो गया है।

भक्ति, सहयोग और सेवा का अनुपम उदाहरण

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में जो सेवा अभियान आरंभ हुआ है, वह राजनीति से ऊपर उठकर एक जनसेवा का उदाहरण बन गया है। अमरकंटक में जहाँ शिवभक्ति की गूंज है, वहीं सेवा की यह मिसाल भी सभी को भावविभोर कर रही है। यह केंद्र केवल भोजन और विश्राम का नहीं, बल्कि आस्था, सहयोग और सामूहिक चेतना का प्रतीक बन गया है।

सीएम हेल्पलाइन बनी सहारा

रायपुर। सीएम हेल्पलाइन सीजी 1076 में दर्ज शिकायत के माध्यम से लगातार 7 वर्षों से आधार कार्ड बनवाने के लिए भटक रहे युवा मुकुंद धीमर को आखिरकार आधार कार्ड प्राप्त हो गया। जिला प्रशासन द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हैदराबाद कार्यालय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ। आधार कार्ड नहीं होने के कारण मुकुंद धीमर बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा पा रहे थे। साथ ही राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाने के कारण उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन सीजी 1076 में शिकायत दर्ज कराई।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

बायफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया तो टावर पर चढ़ी युवती

सूरजपुर। जिले के चांदनी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती अपने प्रेमी के फरार होने से नाराज होकर थाना परिसर के अंदर लगे रेडियो टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार, युवती ने अपने प्रेमी के संबंध में पुलिस से शिकायत की थी। युवती का आरोप था कि उसका बॉयफ्रेंड उससे संपर्क नहीं कर रहा है और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। वह पुलिस से प्रेमी को बुलाने और दोनों का विवाह कराने की मांग कर रही थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने उसे थाना बुलाया था।

ट्रेन में फंदे पर लटका मिला कोरबा के युवक का शव

कोरबा। भोपाल से उज्जैन जा रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट के खिड़की पर कोरबा के एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। रात 12 बजे बीना रेलवे स्टेशन के पास गार्ड की नजर शव पर पड़ी। बीना जंक्शन पर ट्रेन को रुकवाया, जहां जीआरपी ने शव को नीचे उतार पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। मृतक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान कोरबा निवासी गुरुवार सिंह (30) के रूप में हुई, जो दोस्तों के साथ उज्जैन गया था। यात्रियों ने युवक के भोपाल से जनरल डिब्बे में अकेले सवार होने व गेट के पास बैठने की जानकारी दी।

महानदी में डूबे ग्रामीण की लाश बरामद, उधर पुल टूटा

रायपुर। धमतरी जिले में अलग-अलग जगह महानदी में लापता हुए 3 लोगों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। बीते दिनों हुई लगातार बारिश के कारण नदी में तेज बहाव था। पुलिस और बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। सि बीच गरियाबंद में उदंती नदी पर बन रहा करीब 9 करोड़ रुपए का निर्माणाधीन पुल ढह गया। रायपुर में खारून नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बस्तर में एनएच-130 पर पुलिया डैमेज होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया।

350 मकानों की जांच, 8 संदिग्ध मिले; एक गिरफ्तार

रायपुर। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए शुक्रवार तड़के पुलिस ने बीएसयूपी कॉलोनियों में सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। सुबह करीब 4:30 बजे शुरू हुए अभियान के दौरान लाभांडी, बीएसयूपी तेलीबांधा (मरीन ड्राइव) और देवार डेरा क्षेत्र के करीब 350 मकानों की तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इनमें मारपीट के मामले में पिछले 8 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। अभियान पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल के निर्देशन और सहायक पुलिस आयुक्त रमाकांत साहू के नेतृत्व में चलाया गया। इस कार्रवाई 80 से अधिक अधिकारी और जवान शामिल रहे।

एक ही सुई से नशा करना पड़ गया भारी 175 युवाओं में फैला एचआईवी संक्रमण

- सरगुजा संभाग में बढ़ा नशीले इंजेक्शन का चलन
- अब जिन्दगी भर लेनी पड़ेगी दवा, विवाह में होगी दिक्कत
- नशा रोकने के पुलिस के तमाम प्रयास विफल

श्रीकंचनपथ समाचार

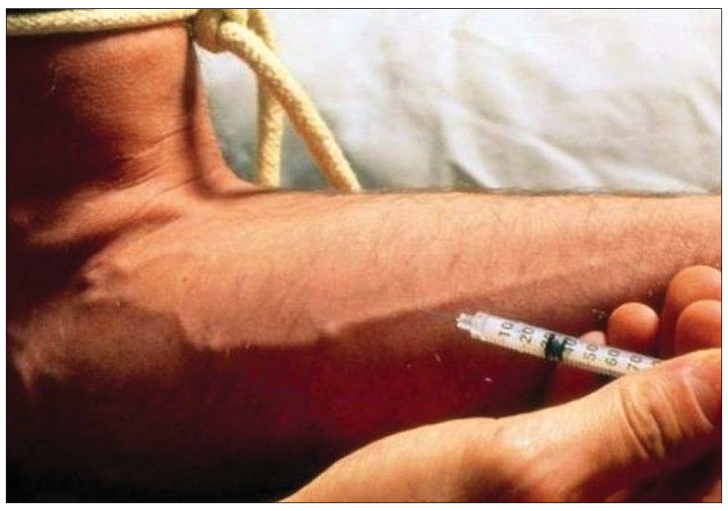

अंबिकापुर। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। नशीले पदार्थों के सेवन के दौरान एक ही इंजेक्शन का सामूहिक उपयोग करने से एचआईवी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 175 लोगों की पहचान की है, जो साझा इंजेक्शन के इस्तेमाल के कारण एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी का उपचार जारी है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शन का चलन लगातार बढ़ रहा है। कई युवक नशे के लिए अपने साथियों के साथ एक ही इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग वर्षों से 'एक मरीज-एक सुई' के सिद्धांत के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन नशे के आदी लोगों पर इसका अपेक्षित असर नहीं दिख रहा है।

उधर, पुलिस नशीले इंजेक्शनों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है तथा विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जब्त भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद इनकी उपलब्धता पूरी तरह नहीं रुक पा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार साझा इंजेक्शन के उपयोग से संक्रमित 175 पंजीकृत मरीजों में सबसे अधिक 108 सूरजपुर जिले के हैं। इसके अलावा कोरिया के 40, एमसीबी के 15, सरगुजा के 11 तथा बलरामपुर के एक मरीज शामिल हैं। विभाग का मानना है कि ऐसे कई अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, जिनकी अभी पहचान नहीं हो सकी है।

दवा लेकर जी सकते हैं सामान्य जीवनः डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता

जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि, कई लोगों द्वारा एक ही इंजेक्शन का उपयोग करने से एचआईवी सहित अन्य रक्तजनित संक्रमण तेजी से फैलते हैं। उन्होंने कहा कि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति नियमित रूप से एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) की दवाएं लेकर सामान्य जीवन जी सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नशे पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है।

एक सप्ताह से बीमार थी छात्रा, घर वालों को नहीं दी सूचना, चल बसी

श्रीकंचनपथ समाचार

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के वनांचल में रहने वाली एक छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा एक सप्ताह से बीमार थी। पर इसकी कोई सूचना उसके घर वालों को नहीं दी गई। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर रात के तीन बजे परिजनों को सूचना दी गई। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मामला बोड़ला विकासखंड का है

परिजनों के अनुसार, बबीता पद्राम नाम की छात्रा अमेरा कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ती थी। दो दिन पहले अचानक रात में उसकी तबीयत खराब हुई थी। उस वक्त छात्रावास अधीक्षिका हॉस्टल में मौजूद नहीं थी। सुबह परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद वे तुरंत पहुंचकर छात्रा को अस्पताल ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन उसे अपने घर ले जाकर अंतिम संस्कार किए।

परिजनों ने मामले में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर छात्रावास अधीक्षिका मौजूद रहती तो, शायद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया जा सकता था।

सामाजिक कार्यकर्ता सुखनंदन धुर्वे ने कहा कि, जिले के वनांचल में रहने वाले बैगा-आदिवासियों के बच्चे भगवान भरोसे ही रह रहे है। उनकी सही देखभाल नहीं हो रही है। जिले के कई छात्रावासों में इस तरह की लापरवाही सामने आ चुकी है। जिस पर सुधार करने की मांग सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारी लक्ष्मी पटेल से किए है।

सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग लक्ष्मी पटेल ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। इस असहज करने वाली घटना को लेकर कलेक्टर की अनुशंसा पर डिप्टी कलेक्टर की अगुवाई में पांच सदस्यीय जांच टीम बनाने की बात कही गई है।

स्कूल में बच्चों के सामने अशोभनीय हरकत प्रायमरी स्कूल का प्रधान पाठक हिरासत में

श्रीकंचनपथ समाचार

जांजगीर-चांपा। जिले के पामगढ़ विकासखंड स्थित डोंगाकोहरौद के शासकीय प्राथमिक विद्यालय से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है। स्कूल के प्रधानपाठक भुवनेश्वर कौशिक पर ड्यूटी के दौरान अशोभनीय हरकत करने और बच्चों के सामने अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा है। घटना से घबराए बच्चों ने घर जाकर पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद आक्रोशित अभिभावक स्कूल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

परिजनों के अनुसार, जब वे विद्यालय पहुंचे तो प्रधानपाठक कथित तौर पर आपत्तिजनक अवस्था में मिले। अभिभावकों ने मौके का वीडियो भी बनाया। इसके बाद तत्काल डायल-112 और पामगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को अपने साथ थाने ले गई।

पुलिस ने बच्चों और उनके अभिभावकों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी प्रधानपाठक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, ग्रामीणों और अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

सड़क दुर्घटना का आरोपी शिक्षा विभाग का कर्मी निलंबित; न्यायिक अभिरक्षा बनी वजह

श्रीकंचनपथ समाचार

पेंड्रा। पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बंधी में 20 जून को हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी (ष्ठश्वह्र) रजनीश तिवारी ने सड़क दुर्घटना के आरोपी शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रद्युम्न तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपी के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार, 20 जून को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सवारियों से भरे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस भीषण दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि कई महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेंड्रा में भर्ती कराया गया था।

मामले की जांच के बाद पेंड्रा पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक प्रद्युम्न तिवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेंड्रा में सहायक ग्रेड-03 के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 191/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 125(ए) और 125(बी) में मामला दर्ज कर 13 जुलाई 2026 को उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही भेज दिया था।

आरोपी के 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रहने के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में प्रद्युम्न तिवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। रिहा होने के बाद उनके मुख्यालय का निर्धारण अलग से किया जाएगा।

बिरगांव कब बन गया जौहर नगर, किसी को भनक तक नहीं लगी, अब हुआ बवाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बिरगांव नगर निगम अंतर्गत आने वाली बंजारी नगर कब जौहर नगर बन गया किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई। जब लोगों ने अपने घरों के आगे जौहर नगर लिखना शुरू किया तब जाकर हिन्दू संगठनों का माथा ठनका। अब उन्होंने इस मामले में विरोध दर्ज कराया है।

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में यहां घरों में लगने वाले नंबर प्लेट में बंजारी नगर की जगह जौहर नगर लिखा जा रहा है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने स्थानीय पार्षद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शुक्रवार को निगम आयुक्त युगल किशोर उर्वाशा को ज्ञापन सौंपा।

विश्वदिनी पाण्डेय ने बताया है कि, उन्हें बंजारी नगर के घरों में जौहर नगर के नाम से नंबर प्लेट लगाए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद वे लोग स्थानीय पार्षद तथा अन्य हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के साथ मिलकर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए गए।

निगम आयुक्त ने उन्हें बताया कि, गलती से प्रिंट मिस्टेक होने की वजह से बंजारी नगर की जगह जौहर नगर नाम से घरों का नंबर प्लेट लग गयी है। गड़बड़ी सामने आने के बाद घरों से नंबर प्लेट वापस निकाली जा रही हैं। हिंदू संगठन से जुड़े नेता ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के भीतर मकान की नंबर प्लेट नहीं हटायी जाती है, तो वे आंदोलन करेंगे।

हिंदू नेता ने नगर निगम के बगैर किसी प्रस्ताव के बंजारी नगर का नाम परिवर्तन किए जाने को लेकर जानबूझकर साजिश करने का आरोप लगाया है। हिंदू नेता के अनुसार पूर्व के गायत्री नगर का नाम इसी तरह से साजिश कर गाजी नगर किया गया। उन्होंने गाजीनगर का नाम पुनः गायत्री नगर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

लूट के कुछ ही देर बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। इस मामले के मास्टरमाइंड कनवर बाग को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वारदात में शामिल उसके तीन साथी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

पुलिस के मुताबिक, अजीत नाडार ने चौकी रामनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 जुलाई 2026 की शाम करीब 6:30 बजे उनका बेटा दुकान जाने के लिए घर से निकला था। गोपालनगर पहुंचने पर मोहल्ले का रहने वाला कनवर बाग अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा।

आरोपियों ने पहले युवक से अश्लील गाली-गलौज की, फिर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की और उसके पास रखे कैश लूटकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर गुढ़ियारी थाना में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) दीपमाला कश्यप ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आदित्य पांडेय, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा और रामनगर चौकी प्रभारी को आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

पुलिस टीम ने पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के साथ तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी कनवर बाग की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है।

पुलिस का कहना है कि, फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लूट में इस्तेमाल किए गए सामान और कैश की बरामदगी की जाएगी। मामले में आगे की जांच जारी है।

रायपुर सेंट्रल जेल में लगाई सेंध; प्याज में गांजा, साबुन की टिकिया में नशीली गोलियां

श्रीकंचनपथ समाचार

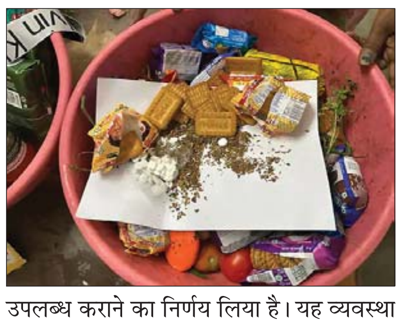

रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में बंदियों तक प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने के लिए परिजनों की ओर से अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों का खुलासा हुआ है। मुलाकात के दौरान कुछ लोगों ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के भीतर नशीले पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्री छिपाकर जेल में पहुंचाने की कोशिश की।

हालांकि, जेल प्रशासन की सघन तलाशी और सतर्क सुरक्षा व्यवस्था के कारण ऐसे सभी प्रयास विफल कर दिए गए। प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई।

इन घटनाओं के बाद जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बंदियों के दैनिक उपयोग की कुछ चयनित सामग्रियां अब सीधे जेल कैंटीन के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था फिलहाल अस्थायी रूप से लागू की गई है।

जेल प्रशासन के मुताबिक, परिजन बंदियों से मुलाकात के दौरान सीलबंद बिस्किट के पैकेटों में छेड़छाड़ कर उनके भीतर तम्बाकू और नशीली टैबलेट रख देते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ लोग प्याज को भीतर से सावधानीपूर्वक खोलकर उसे खोखला कर देते थे। इसके अंदर गांजे की छोटी-छोटी पुड़ियां भरने के बाद उसकी ऊपर सतह को फिर से पुरानी तरह से पैक कर दिया करते थे।

जेल प्रशासन ने बताया कि साबुन की टिकिया का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित सामग्री छिपाने के लिए किया जा रहा था। साबुन को भीतर से काटकर या खोखला कर उसमें नशीले पदार्थ अथवा अन्य प्रतिबंधित सामग्री रखी जाती थी। बाद में उसे दोबारा इस तरह तैयार किया जाता था कि बाहरी रूप से उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ दिखाई न दे।

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों को देखते हुए जेल प्रशासन ने एहतियातन बंदियों के दैनिक उपयोग की कुछ चयनित सामग्रियां अब जेल कैंटीन से ही उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। हालांकि, अन्य सभी स्वीकृत सामग्री पहले की तरह नियमानुसार बंदियों के परिजन उपलब्ध करा सकेंगे।

दबंगों ने किया मजबूर तो खेत में साड़ी की आड़ लगाकर कराया प्रसव

श्रीकंचनपथ समाचार

अंबिकापुर/प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के धुरिया गांव का रास्ता बंद होने के कारण 108 एंबुलेंस गर्भवती महिला तक नहीं पहुंच सकी। मजबूरी में परिजन उसे खेतों के रास्ते पैदल एंबुलेंस तक ले जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही प्रसव पीड़ा तेज हो गई। तब महिलाओं ने साड़ी व चादर से घेरा बनाया और खेत में ही गर्भवती का प्रसव कराया। बाद में जच्चा और नवजात को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत सामान्य बताई गई है।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के कारण पिछले करीब तीन महीने से उनके घर तक आने-जाने का रास्ता बंद है। कई बार नायब तहसीलदार कार्यालय में आवेदन दिया। हाल ही में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक रास्ता नहीं खुल पाया।

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कपिल देव पैकरा ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस घर तक क्यों नहीं पहुंच सकी, इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)

संयुक्त कलेक्टोरेट परिसर, जिला-बालोद (छ.ग.)
Phone No.:-07749-223922, E-Mail ID :- dpobalod@gmail.com

-: ईश्तहार :-

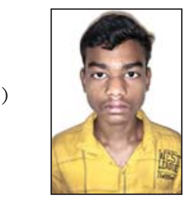

1. बच्चे का नाम - सुनील
2. बच्चे का प्राप्ति दिनांक - 13/12/2024
3. संस्था - शासकीय बालगृह (बालक) दुर्ग, जिला दुर्ग
4. रंग - सांवला
5. उम्र - 14 वर्ष लगभग

उक्त बालक दिनांक 13/12/2024 को बालक कल्याण समिति बालोद के आदेश क्रमांक/125/बा.क.समि./2025 बालोद दिनांक 05/05/2025 से अस्थाई संरक्षण हेतु शासकीय बालगृह (बालक), दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में निवासरत है। बालक का उम्र 14 वर्ष लगभग ऊंचाई - 150 सेमी, वजन - 27 किलोग्राम, रंग - सांवला है, जो किसी हिन्दी भाषा बोलता है। अपने बारे में पुरी जानकारी नहीं दे पाता है। उक्त बालक के संबंध में अथवा बालक के परिवार के संबंध में किसी को जानकारी प्राप्त होती है तो कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बालोद (फोन नम्बर-07749-223941, 223931, 7987063763) में जानकारी प्रदान कर सकते है।

जी-262702476/2

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला - बालोद (छ.ग.)

दो युवकों के पेट के आरपार हो गया पाइप

बिलासपुर। कानन पेंडारी से 200 मीटर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर रात भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी क्षतिग्रस्त रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि रेलिंग का दो इंच मोटा लोहे का पाइप दो युवकों के पेट के पार हो गया। बाइक (सीजी 28 एस 8172) पर जरहागांव के ग्राम पेंड्रीडीह निवासी प्रियांशु ज्ञानिक (24), वेदांत जॉन (22) और अब्राहम जॉन सवार होकर मुंगेली जा रहे थे। बाइक की रफ्तार लगभग 90 किमी प्रति घंटा थी। वेदांत ने खुद ही पेट से पाइप निकाला, जबकि प्रियांशु के पेट में पाइप धंसा रहा। तीसरे साथी अब्राहम को मामूली चोटें आईं। राहगीर गजेंद्र ठाकुर ने 11:08 बजे सूचना दी। 5 मिनट में पहुंची डायल-112 व सकरी पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने घायलों को सिम्स पहुंचाया।

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान
निखार बैंगल
मो.- 9826186026
Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

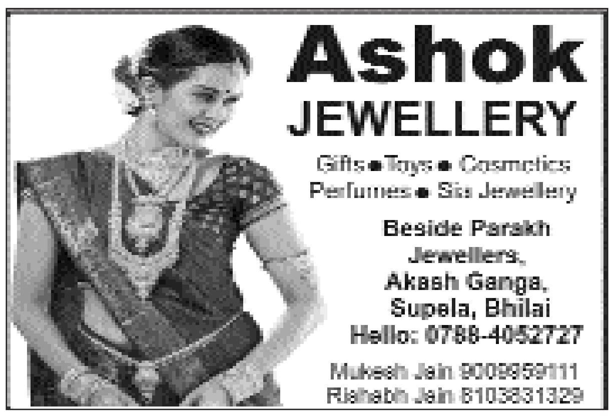

Ashok JEWELLERY
Gifts • Toys • Cosmetics
Perfumes • Sis Jewellery
Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले, पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री साय ने की मुलाकात, छत्तीसगढ़ के विकास और 'बस्तर विजन' पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखा बदलते बस्तर का रोडमैप

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प तथा राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बदलते छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए राज्य की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा, विश्वास और विकास की समन्वित रणनीति के परिणामस्वरूप बस्तर आज व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दशकों तक नक्सल हिंसा और विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाला यह क्षेत्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, बिजली, हवाई संपर्क, आजीविका, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस परिवर्तन को स्थायी बनाते हुए बस्तर को विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय वनस्पतियों एवं पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान की समृद्ध विरासत है। राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से चिकित्सा, अनुसंधान, शिक्षा और औषधीय वनस्पतियों पर आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नई संभावनाएं विकसित होंगी।मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में आए परिवर्तन की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े 421 स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है। जिन गांवों में कभी बच्चों के लिए नियमित शिक्षा तक पहुंच बड़ी चुनौती थी, वहां अब स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में भी राज्य सरकार कार्य कर रही है।

इसका उद्देश्य दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवासीय सुविधाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री साय ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ ने निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर 10.42 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया है। अब अगले चरण में 14 लाख और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित 'लखपति दीदी सम्मेलन' की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ?500 करोड़ के राज्य एआई मिशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शासन की सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की सुदृढ़ होती वित्तीय स्थिति और राजस्व वृद्धि से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ ने वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित करते हुए राजकोषीय एवं राजस्व घाटे में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। राज्य में जीएसटी राजस्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं खनिज राजस्व में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

राजनांदगांव में 10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना के लिए मंजूरी का अनुरोध

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग 10,500 करोड़ की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है तथा राज्य सरकार के स्तर की आवश्यक स्वीकृतियां भी पूरी की जा चुकी हैं। इस परियोजना के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता और बेहतर होगी। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक निवेश, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार तथा सहायक आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

461 गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए मांगी विशेष सहायता

मुख्यमंत्री साय ने बस्तर सहित संवेदनशील क्षेत्रों के ऐसे 461 गांवों का विषय भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा, जहां पूर्व में सुरक्षा एवं भौगोलिक कारणों से विद्युत ग्रिड पहुंचाना संभव नहीं हो पाया था और वर्तमान में ऑफ-ग्रिड माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इन गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थायी विद्युत आपूर्ति से इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, आजीविका और लघु उद्यमों के विस्तार को गति मिलेगी तथा दूरस्थ अंचलों में विकास की प्रक्रिया और मजबूत होगी।

बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी ने दिया बदलाव का संदेश

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी ने पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। खेलों के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिला है और शांति, विश्वास तथा सामाजिक सहभागिता को भी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बस्तर की नई पहचान खेल, संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन, उद्यमिता और विकास से निर्मित हो रही है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य में तेजी से बदल रहे औद्योगिक परिदृश्य की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ को लगभग ?8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें अनेक परियोजनाओं पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को परंपरागत क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों की ओर ले जाया जा रहा है। राज्य में पहली बार एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, ग्लोबल बीपीओ, गारमेंट, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा इंट्राऑक्यूलर लेंस निर्माण जैसे नए क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निवेशों से राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधता आने के साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी निर्मित होंगे।

5,542 गांवों तक पहुंच रहा विकास, लगभग 39 लाख लोगों को लाभ

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री के समक्ष 'बस्तर विजन' की विस्तृत जानकारी रखते हुए बताया कि 'नियद नेल्ला नार 2.0' और 'बस्त मुन्ने' के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में शासन की योजनाओं और सेवाओं का व्यापक क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे लगभग 39 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राशन, आयुष्मान भारत, जनधन खाते, वनाधिकार, प्रधानमंत्री आवास सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ और पूर्व में अत्यधिक संवेदनशील रहे गांवों में प्रशासन की पहुंच बढ़ने से शासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' में 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच

मुख्यमंत्री साय ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' के अंतर्गत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और आवश्यकता के अनुरूप उन्हें चिकित्सा सेवाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर में चिकित्सा अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ गीदम में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार नए मेडिकल कॉलेजों और आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है।

सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क से बदल रही बस्तर की तस्वीर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर के स्थायी विकास के लिए कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसी दृष्टि से सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि लगभग ?3,513 करोड़ की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेललाइन परियोजना पर कार्य आगे बढ़ रहा है। इस रेल संपर्क से बस्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। जगदलपुर से नियमित हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के अंतिम चरण की प्रगति तथा इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी।

बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड बनाने की दिशा में प्रयास

मुख्यमंत्री साय ने बस्तर की अनूठी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन संभावनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे विश्वस्तरीय प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और प्रमुखता से स्थापित करने के लिए अधोसंरचना एवं सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर का विकास उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति के संरक्षण के साथ किया जा रहा है, विकास का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित हों।

निवेश अनुकूल वातावरण में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पहचान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि निवेशकों के लिए पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद व्यवस्था विकसित करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में नियामकीय सुगमता और संस्थागत वातावरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026' की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य ने उद्योगों और उद्यमियों के लिए जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था, सेल्फ सर्टिफिकेशन और समयबद्ध अनुमतियों को कानूनी आधार प्रदान किया है। निवेशकों को निश्चितता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित व्यवस्था मिल रही है।

मुख्यमंत्री साय की पहल से जशपुर को सड़क विकास की बड़ी सौगात

चार ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 8.44 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में जशपुर जिले को एक और महत्वपूर्ण सौगात मिली है। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत जिले के चार प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए कुल 8 करोड़ 44 लाख 68 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों के निर्माण से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा आवागमन के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। शासन के इस निर्णय से क्षेत्रवासियों में उत्साह और खुशी का माहौल है।

राज्य शासन द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार बुलडेगा से रेचवाघाट पहुंच मार्ग (1.20 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 1 करोड़ 23 लाख 77 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा दैनिक आवागमन में आने वाली परेशानियां दूर होंगी।

इसी प्रकार खुंटापानी से सलियामुड़ा पहुंच मार्ग (3 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 3 करोड़ 46 लाख 67 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मार्ग कई गांवों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क बनने से विद्यार्थियों को विद्यालय, मरीजों को स्वास्थ्य संस्थानों तथा किसानों को कृषि उपज के परिवहन में बेहतर सुविधा मिलेगी।

कोसमभावना से बनगांव पहुंच मार्ग (1.20 किलोमीटर) के निर्माण, जिसमें पुल-पुलिया का निर्माण भी शामिल है, के लिए 1 करोड़ 43 लाख 84 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से विशेषकर बरसात के दौरान आवागमन बाधित होने की समस्या का स्थायी समाधान होगा और ग्रामीणों को पूरे वर्ष सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त बुलडेगा मेन रोड से सुकबासुपारा होते हुए भिंजपुर पहुंच मार्ग (2.50 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख 40 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के अनेक गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

अरुणाचल मॉडल पर बस्तर में सड़क निर्माण की मांग, मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से किया आग्रह

PMGSY-IV में 10 किमी क्लस्टर की विशेष व्यवस्था का प्रस्ताव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया सकारात्मक आश्वासन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया। बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित थे।

इस दौरान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर सहित प्रदेश में ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर के अनेक गांव घने जंगलों, पहाड़ियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केवल 500 मीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है। इस व्यवस्था के कारण बस्तर के अनेक छोटे और दूरस्थ गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि अरुणाचल प्रदेश की तरह बस्तर में भी 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर मानने की विशेष अनुमति दी जाए, ताकि अधिक से अधिक गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद के दौर से निकलकर तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में बेहतर सड़क संपर्क क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं हैं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला हैं। इसलिए बस्तर की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जानी चाहिए।

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को गंभीरता से सुना और इस पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर जैसे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीरामजी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण जैसे कार्य प्रभावी ढंग से हो रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 1,500 आवासों का निर्माण एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य और अधिक गति से आगे बढ़ेंगे।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे शासन की योजनाओं का लाभः राज्यपाल

जल संरक्षण, पर्यावरण, जैविक खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं सुशासन पर दिया विशेष जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने अपने दो दिवसीय रायगढ़ प्रवास के प्रथम दिवस जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। जिला कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में उन्होंने जल संरक्षण, पौधारोपण, पर्यावरण संवर्धन, जैविक कृषि, स्वच्छता, योग, टीबी उन्मूलन, आजीविका, सहकारिता, सड़क सुरक्षा सहित बीस से अधिक बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल डेका ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ.सी.आर.प्रसन्ना, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका ने जिले में चल रहे पौधारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए विशेष रूप से अमृत सरोवर परिसरों में लगाए गए पौधों की संख्या एवं उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का दीर्घकालीन संकल्प है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करने तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक परिसरों में व्यापक पौधारोपण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि जिले की औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से 10 हजार पीपल के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें आमजन तक पहुंचाकर रोपित कराया जाएगा। राज्यपाल ने सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने और मृदा की प्रकृति के अनुरूप पौधारोपण एवं जल संरक्षण की समेकित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल श्री डेका ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेते हुए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जीवामृत, कम्पोस्ट, ग्रीन मैन्योर, मदर कल्चर एवं ब्लू-ग्रीन तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न जैविक एवं औषधीय फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े किसानों को खेती के साथ डबरी निर्माण एवं मत्स्य पालन अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा, ताकि कृषि आय के अतिरिक्त आय के अन्य स्रोत भी विकसित हो सकें।

जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने पर दिया जोर

राज्यपाल डेका ने जिले में जल संरक्षण एवं जल संचयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेते हुए कहा कि वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अन्य राज्यों असम, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में जल संरक्षण के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए वर्षा जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग तथा जल स्रोतों के संरक्षण के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पुराने कुओं, बावड़ियों तथा अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाया जाए, जिससे भू-जल स्तर में स्थायी सुधार हो सके।

बस्तर के 461 पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों तक बिजली पहुंचाने की पहल, केंद्र से विशेष सहायता का आग्रह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों के 461 दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों तक ग्रिड बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से 435 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सौंपते हुए कहा कि जिन गांवों में वर्षों तक नक्सल हिंसा के कारण विकास नहीं पहुंच सका, वहां अब बिजली जैसी बुनियादी सुविधा पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 973 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार से तीन वित्तीय वर्षों में सहायता मांगी गई है। वर्ष 2026-27 में 85 करोड़ रुपये, 2027-28 में 250 करोड़ रुपये और 2028-29 में 100 करोड़ रुपये, यानी कुल 435 करोड़ रुपये केंद्र से अपेक्षित हैं, जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत इस प्रस्ताव को विशेष प्रकरण मानते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि बस्तर के दूर-दराज़ गांव भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि बिजली पहुंचने से आदिवासी परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा छोटे उद्योगों को नई गति मिलेगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत प्रस्ताव प्राप्त होते ही उस पर तत्काल स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए धनराशि की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी और केंद्र सरकार बस्तर के विकास के लिए पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब विकास, विश्वास और नई संभावनाओं की पहचान बन रहा है। इन 461 गांवों तक बिजली पहुंचना उसी परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950